①

अर्थव्यवस्था का सामान्य अध्ययन

P D C E

1776
अर्थशास्त्र — एडम स्मिथ — wealth of nation
पूंजीवादी (

Economics — सामाजिक विज्ञान

ग्रीक — okio Nomous — अर्थ

अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के okio Nomous से हुई है जिसका अभिप्राय है घर का नियम। व्यावहारिक रूप से अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत मनुष्य अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरन्तर अध्ययन करता है।
इस अध्ययन में मनुष्य के द्वारा निम्न दो प्रकार की क्रियाएँ निष्पादित की जाती हैं।

1) आर्थिक क्रिया (धन कमाने के लिए की गयी क्रियाएँ)
2) सामाजिक क्रिया (सामाजिक उद्देश्य)

Note: अर्थशास्त्र का जनक – एडम स्मिथ, wealth of Nation 1776

अर्थव्यवस्था : अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें उत्पादन, वितरण एवं उपभोग के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाये, अर्थव्यवस्था कहलाती है।

Note अर्थव्यवस्था अपने आप में एक संपूर्ण शब्द नहीं है जब तक कि इसके पहले किसी क्षेत्र अथवा समूह का नाम न जोड़ा जाये। जैसे- यूरोप की अर्थव्यवस्था, राज॰ की अर्थव्यवस्था, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था

प्रकार :- 1) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था :- जनक – एडम स्मिथ (america)
अर्थव्यवस्था का वह प्रकार जिसमें उत्पादन पर सर्वाधिक जोर दिया जाता है। ताकि max. लाभ प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में नियम एवं विनियम बाजार के द्वारा बनाए जाते हैं।

Scanned by CamScanner

2) समाजवादी अर्थव्यवस्था :- वह अर्थव्यवस्था जो उत्पादन पर नहीं बल्कि वितरण पर जोर देती है तथा सामाजिक कल्याण के लिए जिसमें नियम सरकार द्वारा बनाए जाते हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। (जनक → कार्ल मार्क्स Russia)

3) मिश्रित अर्थव्यवस्था :- जनक – प्रो. जान मेनार्ड कीन्स (England) → Theory of Employment investment money

↓ आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक

वह अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी व पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाये जाते हैं। उदा.- Indian economy

अन्य प्रकार:- 1) बन्द अर्थव्यवस्था :- वह अर्थव्यवस्था जिसमें घरेलू नीतियों पर अधिक ज़ोर दिया जाता हो तथा आयात-निर्यात नीति पर कठोर प्रतिबन्ध लगाए गए हों।

उदा.- वर्ष 1947-91 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था

2) खुली अर्थव्यवस्था :- वह अर्थव्यवस्था जो बन्द नहीं है।

उदा.- 1991 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था

भारतीय अर्थव्यवस्था:- भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण है जिसमें उत्पादन क्षमता के अनुसार तथा वितरण आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 व 46 में संसाधनों के सबके हितों के में उपयोग की बात कही गई है तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का उल्लेख करती है अत: कह सकते हैं कि संविधान निर्माण के समय से ही I.E. मिश्रित अर्थव्यवस्था रही 1947-90 तक समाजवादी तथा 1991 से वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रही है।

Note: 1990 तक भारत के सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में सर्वाधिक हिस्सा कृषि का था परन्तु आर्थिक सुधारों के बाद कृषि का हिस्सा सबसे कम हो चुका है। सेवाओं का हिस्सा सर्वाधिक है।

Scanned by CamScanner

## विश्व के महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संघ :-

1944 - 44 मित्र राष्ट्र (USA, UK)

↓

ब्रेटनवुड (हेम्पशायर, अमेरिका)

- IMF — अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
- WB — विश्व बैंक
- ~~I~~WTO — अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (USA - युनाइटेड, Russia)

IMF + WB → 1944 → ब्रेटनवुड जुड़वाँ

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात् तत्कालीन मित्र राष्ट्र अमेरिका के ब्रेटनवुड नामक शहर में एकत्र हुए तथा द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् वैश्विक, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए निम्न 3 संगठनों की स्थापना का प्रस्ताव पेश किया गया।

1) आर्थिक सुधार के माध्यम से दुनिया का विकास = IMF
2) दीर्घकालीन पुर्ननिर्माण से विश्व का विकास = WB
3) अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार के माध्यम से दुनिया का विकास = ITO

**Note:** USSR एवं USA के मध्य विवाद के कारण ITO की स्थापना नहीं हो सकी

**Note:** चूंकि ब्रेटनवुड कान्फ्रेंस में IMF व WB सर्वसम्मति से स्थापित किये गए अतः दोनों संस्थाओं को ब्रेटनवुड जुड़वाँ कहते हैं।

1) IMF (वाशिंगटन) → स्थापना - 27 दिसम्बर 1945, ब्रेटनवुड कान्फ्रेंस
→ कुल सदस्य देश - 189 (12 April 2016 को ~~जोर्डन~~ नौरू को 189वां सदस्य देश बनाया गया)
→ अध्यक्ष - क्रिस्टीना लेगार्ड (~~जर्मनी~~) फ्रांस

प्रथम निदेशक/अध्यक्ष - केमिथ गट्ट (~~जर्मनी~~) फ्रांस

IMF का अध्यक्ष सदैव ~~जर्मनी~~ फ्रांस का नागरिक होता है।

Scanned by CamScanner

→ ब्रेटनवुड कान्फ्रेंस में 1945 में ब्रिटेन के प्रतिनिधि – चर्चिल (PM), प्रो० कि (अर्थशास्त्री), चितरंजनदास (CD) देशमुख

→ IMF की संरचना - त्रिस्तरीय संरचना है। जिसमें अध्यक्ष, कार्यकारी परिषद एवं बोर्ड ऑफ गवर्नेंस शामिल हैं।

→ IMF की सदस्यता ग्रहण करने से पूर्व प्रत्येक सदस्य देश को निश्चित अंशदान करना पड़ता है तथा इसी अंशदान के आधार पर उस देश को वोटिंग शक्ति प्राप्त होती है (विकसित देशों का प्रभुत्व अधिक)

→ अंशदान के हिसाब से IMF के प्रमुख 10 देश
- USA
- जापान
- फ्रांस
- जर्मनी
- ब्रिटेन (U.K.) इटली
- चीन
- रूस
- ब्राजील भारत – 9 वें (2016 के बाद)
- ब्राजील, UAE, CANADA

2016 में किये गए सुधारों के कारण कनाडा एवं UAE प्रमुख 10 देशों की सूची से बाहर हो चुके हैं तथा ब्राजील एवं भारत शामिल हो चुके हैं।

→ IMF में भारत, श्रीलंका, भूटान एवं बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व करता है।

→ वर्तमान में IMF के भारतीय प्रतिनिधि – रघुराम राजन (RBI गवर्नर)
सुबीर गोकर्ण (वित्त मंत्री । सचिव)

IMF के कार्य :- 1) ऋण देना : IMF अपने सदस्य देशों की भुगतान संतुलन को सन्तुलित करने के लिए अल्पकालीन सस्ता व्यवस्थित ऋण प्रदान करता है।

ऋण प्राप्त करने के लिए IMF की निम्नलिखित शर्तें होती हैं -

→ ऋण प्राप्त करने से पूर्व की शर्त :→ सदस्य देश को सुदृढ़ लोकतंत्र, सुशासन एवं मानवाधिकार को अपनाना पड़ता है।

→ ऋण प्राप्त करने के बाद की शर्त : सदस्य देशों में आर्थिक स्थिरता एवं LPG का होना आवश्यक है।
|
उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण

Scanned by CamScanner

⑤

**Note** IMF सदस्य देशों को रियायती दरों पर ऋण प्रदान करता है (अधिकांशत अल्पविकसित देशों को)

2) विश्व की अर्थव्यवस्था का नियमन करना - इस हेतु IMF निम्नलिखित 3 रिपोर्ट प्रकाशित करता है -

(A) वैश्विक आर्थिक परिदृश्य
(B) क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य
(C) वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

**Note** हाल ही में प्रकाशित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में IMF ने भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न 3 समस्याओं का उल्लेख किया है

1) Economic Overheating :- वह अवस्था जब देश में उत्पादन बढ़ता हो पर साथ ही मंहगाई भी बढ़ती हो।

कारण- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Pds) में कमी का होना.

2) Dutch Disease (हॉलैण्ड की बीमारी) :- वह अवस्था जब निवेश बढ़ा हो परन्तु निर्यात में गिरावट हो।

कारण: निर्यात की नीति में कमी (भारत में मेक इन इण्डिया)
आधारभूत संरचना का अभाव (राज. में रिसर्जेंट राज.)
भ्रष्टाचार

3) Asset Bubble :- वह अवस्था जिसमे सेवाओं का मूल्य बढ़ा हो परन्तु सुविधाएँ नहीं बढ़ी हो।

कारण:- काला धन एवं कठोर ब्याज नीति

क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट मे हाल ही में IMF से भारत को विश्व का आशा का बिन्दु बताया है

वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट मे भारत मे विनिर्माण व बैंकिंग क्षेत्र संकट में बताये गये है।

Scanned by CamScanner

⑥

3) WB (WORLD BANK) स्थापना : 1945, 27 Dec.

सदस्य देश : 189

अध्यक्ष : किम योंग जिम (अमेरिकी मूल के नागरिक)

प्रथम : यूजनेसी मेयर (अमेरिका)

Note विश्व बैंक का अध्यक्ष सर्वदा अमेरिकी मूल का व्यक्ति होता है।

Note आर्थिक मामलों में दुनिया की सर्वोच्च संस्था, अधिकतर देश विश्व बैंक के अनुसार ही अपना बजट बनाते हैं।

संरचना : IMF के समान (अंशदान को छोड़कर)

संगठक, संघटक WB के : (1) IBRD (International Bank for Reconstruction & Development)

(अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक)

→ स्थापना 1945

→ यह संस्था अपने सदस्य देशों को भौतिक संसाधनों के विकास के लिये दीर्घकालीन सस्ता ऋण प्रदान करती है।

जैसे : सड़क के विकास के लिए, रेलवे के विकास के लिए, हवाई अड्डा एवं पुल निर्माण के लिये, नदी की सफाई (गंगा की सफाई), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

Note भारत की इस संस्था में हिस्सेदारी 7 वें नम्बर पर है।

(2) अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी (International Development Agency)

→ विश्व बैंक की उदार खिड़की, स्थापना - 1960

क्योंकि विश्व बैंक का कोई भी ऋण इससे सस्ता नहीं होता

→ यह संस्था सदस्य देश को मानवीय संसाधनों के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। जैसे कुशलता विकास, तकनीकी विकास, जनजाति विकास कार्यक्रम इत्यादि।

Scanned by CamScanner

3| अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (International financial corporation)

→ स्थापना - 1956

→ यह संस्था सदस्य देशों की उन निजी संस्थाओं को वाणिज्यिक ऋण प्रदान करती है जो विकास के कार्यक्रम में लगी हुई है।

Note IFC के द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम India infrastructure & Development programm
बेंगलुरु मेट्रो परियोजना, हैदराबाद मे ग्रीन फील्ड airport, राज्य में सड़कों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सहायता

4| MIGA – Multilatral investment guarantee Agency
बहुपक्षीय निवेश गारन्टी संस्था

स्थापना - 1988 में, भारत सदस्य 1993 में बना।

→ विश्व बैंक की यह संस्था प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का ऋण प्रदान नहीं करती अपितु यदि कोई विकसित देश, विकासशील अथवा अल्पविकसित देशों में निवेश करता है तो ऐसे निवेश के संबंध में गारंटी प्रदान करने की भूमिका निभाता है।

Note विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत में 1993 में स्थापित विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड (FIPB) MIGA के प्रयासों की ही देन है।

5| IIDSC (International investment dispute settlement centre)
अन्तर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटारा केन्द्र

स्थापना - 1986 में
भारत सदस्य नहीं है।

Note विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भारत ने 83 देशों के साथ द्विपक्षीय BIPA निवेश प्रवर्तन समझौता बनाया है। इसके अंतर्गत विदेशी निवेश को सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी स्वयं भारत सरकार ने दी है।
नेपाल व UAE से वार्ता जारी है

Scanned by CamScanner

⑧ *

3) WTO (World Trade Organisation) विश्व व्यापार संगठन (WTO)

ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में वैश्विक मुक्त व्यापार के लिए ITO नामक संस्था स्थापित करने का प्रस्ताव पेश हुआ परन्तु अमेरिका और सोवियत संघ के विवाद के चलते इसे स्थापित नहीं किया जा सका, तत्पश्चात 1948 में वस्तुओं के मुक्त अंतर्राष्ट्रीय व्यापार (कोई प्रतिबंध नहीं) के लिए GATT (General aggreament on Trade & Tariff) (वस्तु-व्यापार का सामान्य समझौता) नामक संस्था की स्थापना की गयी, परन्तु इस संस्था में भी निम्न कमियाँ थी -

1) इसके द्वारा दिये गए निर्णय बाध्यकारी नहीं थे

2) विकासशील देशों की भूमिका ना के बराबर थी

3) यह केवल वस्तुओं से संबंधित व्यापार के नियम बनाता था जबकि 1980 के दशक में सेवाओं का व्यापार भी होने लग गया था।

उपर्युक्त समस्याओं को सुलझाने के लिए 1 जनवरी 1995 को WTO नामक संस्था की स्थापना की गयी। वर्तमान विश्व में वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त व्यापार से संबंधित नियम WTO के द्वारा ही बनाए जाते हैं।

→ स्थापना - 1 जनवरी 1995

सदस्य - 164 (164 वाँ अफगानिस्तान, 163 वाँ लाइबेरिया (अफ्रीकी देश)

→ संरचना :- इसकी संरचना भी त्रिस्तरीय है जिसमें निम्न स्तर शामिल हैं

1) मंत्रीस्तरीय सम्मेलन - 164 सदस्य देश
- प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार सम्मेलन द्वारा मिलते हैं तथा निर्णय (बहुमत) लिये जाते हैं।

2) सामान्य परिषद - WTO के दैनिक कार्य निष्पादित / संचालित करती है।

3) Director General - 164 सदस्य देशों द्वारा मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में चुने जाते हैं। 4 वर्ष कार्यकाल, पुर्ननियुक्ति हो सकती है

वर्तमान - राबर्टो अझेविदो (ब्राजील)

प्रथम - पीटर सदरलैण्ड (1993-95) (नीदरलैंड)

(9)

## WTO के मंत्रीस्तरीय सम्मेलन -

| | वर्ष | स्थान |
|---|---|---|
| 1 | 1996 | सिंगापुर |
| 2 | 1998 | जेनेवा |
| 3 | 1999 | सिएटल - USA |
| 4 | 2001 | दोहा (चीन को सदस्य बनाया गया) |
| 5 | 2003 | कानकुन (मैक्सिको) |
| 6 | 2005 | हांगकांग |
| 7 | 2009 | जेनेवा |
| 8 | 2011 | जेनेवा (रूस को सदस्य बनाया गया) |
| 9 | 2013 (Imp) | बालि (इण्डोनेशिया) |
| 10 | 2015 | नैरोबी |

Note: WTO वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार के लिये निम्नलिखित 5 समझौतों के माध्यम से नियम बनाता है तथा समस्त सदस्य देशों के इन समझौतों के नियम मानना अनिवार्य है। ये समझौते निम्न प्रकार है -

1) GATT (वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम)

2) GATS (General agreement of Trade in services)
(सेवाओं के व्यापार से संबंधित नियम

3) ~~TREPS~~ TRIPs - Trade related to intelectual property
(बौद्धिक सम्पदा)

4) TRIMs - Trade related to investment & measure
(निवेश के संबंध में नियम)

5) AoA : Agreement on Agriculture (कृषि आधारित समझौता)
(बाली विवाद)

Scanned by CamScanner

**WTO के समझौते :→** (i) वैश्विक मुक्त व्यापार के लिए WTO निम्न समझौतों या समझौतों के माध्यम से नियम बनाता है जो समस्त सदस्य देशों पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं :-

(1) **GATT :** वस्तु व्यापार का सामान्य समझौता
WTO के इस समझौते के अनुसार वस्तुओं के व्यापार पर निम्न प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा सकता है

① **मात्रात्मक नियंत्रण :** वस्तुओं के संदर्भ में कोटा (आरक्षण) व्यवस्था को लागू करना
* WTO ऐसे नियन्त्रण के विरोध में है।

② **गुणात्मक नियंत्रण :** गुणात्मकता के आधार पर वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रण लगा देना जैसे - आयात शुल्क को बढ़ा देना, लाइसेंस व्यवस्था को लागू करना, अन्य किसी प्रकार से व्यापार को प्रतिबंधित करना।
* WTO ऐसे नियंत्रण के विरोध में है।
* WTO के अनुसार घरेलू देश स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं मानवाधिकारों के आधार पर विदेशी वस्तुओं पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं।

वर्तमान में इस आधार पर ~~वर्तमान में~~ लगाये गये Imp. प्रतिबंधों के उदाहरण -
भारत के बासमती चावल पर U.K. में रोक (अत्यधिक यूरिया के कारण)
अत्यधिक मर्करी के कारण भारतीय च्यवनप्राश पर अमेरिका में रोक
भारत के द्वारा मर्करी के आधार पर Maggi पर प्रतिबन्ध
जर्मनी की कारों पर अमेरिका में प्रतिबन्ध
भारतीय कपड़ों पर अमेरिका में प्रतिबन्ध
~~भारतीय~~ अमेरिका, U.K. में भारतीय खेल के सामान के विक्रय पर रोक (बाल-श्रम का उपयोग)

Scanned by CamScanner

(7)

(2) GATS :→ सामान्य सेवा के व्यापार संबंध में समझौता

WTO के अनुसार सेवाओं को निम्न 4 वर्गों में बाँटा गया है –

(1) MODE - I :- बिना विदेश में जाए घरेलू लोगों अथवा संस्था के द्वारा विदेशियों को सेवा प्रदान करना।

उदा॰ - BPO (Business process outsourcing)
KPO (knowledge – 〃 —— )
LPO (Legal – 〃 —— )

(5) श्रम में शामिल करना आवश्यक होता है

(2) MODE - II :- पर्यटन सेवा

(3) MODE - III :- विदेश में कार्यालय स्थापित करके विदेशियों को सेवा प्रदान करना

(4) MODE - IV :- व्यक्तिगत रूप से विदेश में जाकर सेवा प्रदान करना।
Ex. doctor, engineer, singer, actor, पेशेवर

NOTE भारत के लिये MODE-I व MODE-IV महत्वपूर्ण सेवा

NOTE WTO के अनुसार कोई भी घरेलू देश विदेशी सेवाओं पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं लगा सकता।

जैसे– सेवा कर में वृद्धि करके एवं visa के संबंध में कठोर नीति बनाना

NOTE घरेलू देश कुशलता के आधार पर visa के नियमों को कठोर कर सकता है।

Scanned by CamScanner

(12)

(3) TRIPS :- (बौद्धिक संपदा के व्यापार के नियम)

बौद्धिक संपदा :- वह संपति जो बुद्धि से प्राप्त किया जाये। ये सम्पतियाँ अदृश्य एवं अमूर्त होती है।

WTO के अनुसार बौद्धिक संपदाए निम्न प्रकार की होती है।

(1) Copyright :- साहित्य एवं प्रकाशन के संबंध में मूल लेखक अथवा निर्माता को प्राप्त अधिकारों का पंजीकरण, copyright कहलाता है।

* यह अधिकार 20 वर्षों के लिये मिलता है। पुर्नपंजीकरण किया जा सकता है।

(2) पेटेंट :- आविष्कार के संबंध में प्राप्त अधिकार (20 वर्षों के लिए)

(3) Trademark : किसी उत्पाद को विशिष्ट बनाने के लिए कोई नाम, logo या अन्य प्रतीक। (15 वर्ष)

(4) भौगोलिक पहचान (Geographical indication) :→ किसी उत्पाद से पहले भौगोलिक क्षेत्र के नाम का जुड़ना। (15 वर्ष

Note: india के 218 GI वाले उत्पाद WTO में पंजीकृत है

→ राजस्थान के GI :- बीकानेरी भुजिया, कोटा-डोरिया साड़ी, ब्लू पॉटरी, सांगानेरी प्रिन्ट, बगरू का हेण्ड-ब्लॉक प्रिन्ट, कठपुतली नृत्य, मकराना मार्बल, प्रतापगढ़ की थेवा कला,

Note प्रतापगढ़ के राज-सोनी परिवार की देन (भारत का एकमात्र परिवार जिसे सर्वाधिक (8) राष्ट्रीय पुरुस्कार प्राप्त करने वाला परिवार)

2015 में महेश राज सोनी पदम श्री

Note WTO के अनुसार बौद्धिक-संपदाओं में व्यापार होना आवश्यक है।

Scanned by CamScanner

~~(4) TRIMs :-~~

औद्योगिक डिजाइन :- औद्योगिक कम्पनियों के द्वारा औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन का पंजीकरण, औद्योगिक डिजाइन कहलाता है। (10 वर्ष)

व्यापारिक रहस्य :- रसायन एवं दवा के क्षेत्र की कम्पनियों को रासायनिक पदार्थ के संबंध में प्राप्त पंजीकरण। (10 वर्ष)

(4) TRIMs :- WTO का यह समझौता विदेशी निवेश से सम्बन्धित नियमों का उल्लेख करता है। इस समझौते का उद्देश्य है कि घरेलू देश विदेशी निवेश सम्बन्धी नीतियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना करे तथा कच्चे माल को खरीदने की बाध्यता विदेशी उत्पादकों पर ना लगाई जाए (मेक इन इण्डिया में विवाद)

(5) AOA (भारतीय संबंध में सबसे महत्वपूर्ण समझौता)

WTO का यह समझौता कृषि उत्पादकों को दी जाने वाली प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहायता को लेकर नियम बनाता है।

WTO के अनुसार कृषि पर प्रदान की जाने वाली सहायता (सब्सिडी) निम्न चार वर्गों में विभाजित की गयी है।

1) Red Box सब्सिडी :- यह सब्सिडी उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है अतः ऐसी सब्सिडी समाप्त की जाए।
जैसे- मुफ्त जमीन कृषि के लिए देना।

2) Green Box सब्सिडी :- (नार्वे, स्लोवानिया) यह कृषि अनुसंधान पर दी जाती है। ऐसी सब्सिडी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डालती अतः WTO द्वारा कोई आपत्ति नहीं।

3) Blue Box सब्सिडी :- यह सब्सिडी भी उत्पादन पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती है। WTO का नियम कहता है कि इसे कम किया जाये
Ex. ऋण माफी योजना, अकालग्रस्त किसानों को मुआवजा।

Scanned by CamScanner

(14)

(4) Amber box Subsidy :- यह सब्सिडी उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है अतः WTO का नियम है कि इसे कम करते हुए शून्य किया जाये। विकासशील देश के लिए है

उदा.- बीज दी जाने वाली सहायता, सिंचाई पर दी जाने वाली सहायता, उर्वरकों पर दी जाने वाली सहायता।

* इस सब्सिडी की दर को WTO के बालि सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया

उपर्युक्त प्रस्ताव पर विकासशील एवं विकसित देशों के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ जिसके समाधान के लिए इसके समझौते में शांति वाक्यांश जोड़ा गया जिसकी महत्वपूर्ण बातें निम्न

1) समस्त सदस्य देश इस समझौते पर 2014 तक sign करेंगे (समयसीमा 2017 तक स्थगित)

2) हस्ताक्षर ना करने के समय तक विकसित देश विकासशील देशों के विरुद्ध कृषि को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते।

नैरोबी शिखर वार्ता :- Dec. 2015 में आयोजित WTO की शिखर वार्ता में निम्न निर्णय लिये गये -

1) अल्पविकसित देशों के विकास की जिम्मेदारी विकसित एवं विकासशील देशों की होगी।

2) अल्पविकसित देशों के कृषि उत्पादों एवं वस्त्र उद्योग के उत्पादों पर कोई भी देश किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता (व्यापार सरलीकरण समझौता)

* 2015 में भारत के प्रतिनिधि निर्मला सीतारमण।।

Scanned by CamScanner

# आर्थिक संवृद्धि एवं विकास
## {Economic Growth & Development}

* किसी देश की अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन, उस देश की आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास की दर से किया जाता है।

→ किसी देश की ~~आर्थिक~~ economy में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को आर्थिक संवृद्धि कहा जाता है।

जैसे :- स्कूलों की संख्या में वृद्धि, सड़कों की लम्बाई में वृद्धि, मकानों एवं अस्पताल की संख्या में वृद्धि

→ किसी देश की economy में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को उस देश का आर्थिक विकास कहा जाता है।

जैसे :- गाँवों में सड़कों का विकास।

* आर्थिक संवृद्धि सरकार एवं निजी क्षेत्रों के प्रयासों की देन होती है जबकि आर्थिक विकास के लिए प्रयास सरकार द्वारा किये जाते हैं।

→ आर्थिक संवृद्धि एवं विकास में पाये जाने वाला अन्तर ही आर्थिक विषमता कहलाता है।

**Note:** इस आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए भारत में सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन किया जाता है। ( पंचवर्षीय योजना )

### आर्थिक संवृद्धि के मापन के आधार :-

1) GDP (सकल घरेलू उत्पाद) : किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत ~~वित्तीय~~ वित्तीय वर्ष की अवधि में किया गया समस्त उत्पादन चाहे वह घरेलू अथवा विदेशी नागरिकों ने किया हो।

**Note:** भारत की GDP के क्षेत्र – 3
- प्राथमिक क्षेत्र – कृषि = 16.8%
- द्वितीयक क्षेत्र – व्यापार, व्यवसाय, उद्योग – 28%
- तृतीयक क्षेत्र – सेवा = 54.5

**Note:** यदि किसी देश की GDP बढ़ती है तो उसका अर्थ है कि उस देश के बाजार का आकार बढ़ा है।

→ GDP के आधार पर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है (बाजार मूल्य पर)

2) GNP (सकल राष्ट्रीय उत्पादन) भारतीय नागरिकों के द्वारा समस्त विश्व में किया गया उत्पादन चाहे वह भारत में किया गया हो अथवा विश्व में

Note: IMF व WB, GNP के आधार पर ही किसी देश का आर्थिक मूल्यांकन करता है।

सूत्र: GNP = GDP + (X − M)

(X → निर्यात, M → आयात)

NOTE: बन्द अर्थव्यवस्था में सदैव GNP = GDP

GNP = GDP + NFIA (Net factor income from abroad)

NFIA → X − M

NOTE: किसी देश में GNP के बढ़ने से उस देश की बाह्य शक्ति में वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है।

3) NDP (शुद्ध घरेलू उत्पादन): किसी देश की GDP में से ह्रास अथवा क्षरण की मात्रा को कम करने के पश्चात शेष उत्पादन NDP कहलाता है।

Note: किसी भी वस्तु अथवा साधन में निरन्तर उपयोग के कारण होने वाले क्षरण (कमी) को मूल्य ह्रास कहा जाता है।

Note: यही क्षरण उत्पादन की लागत कहलाती है जो निम्न प्रकार की होती है

लागत के प्रकार ↳ 1) साधन लागत (factor cost) → उत्पादन के सभी साधनों पर किया गया व्यय।

- प्राथमिक लागत
  - → भूमि → किराया
  - → श्रम → मजदूरी
  - → पूंजी → ब्याज...
- द्वितीयक लागत
  - ↓ सेवा → बीमा, banking, परिवहन, ऊर्जा और संचार

(18)

2) बाजार लागत ( Market cost ) :-

साधन लागत + अप्रत्यक्ष कर - सब्सिडी

शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ~~साधन लागत~~ = अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी

शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (NIDT)
Net Indirect tax

साधन लागत + NIDT = बाजार लागत

Note बाजार मूल्य = बाजार लागत + अपेक्षित लाभ

चूंकि सरकार कभी भी लाभ के लिए कार्य नहीं करती अत: सरकार के लिए
बाजार लागत = बाजार मूल्य

Note बाजार लागत को कम करने के उपाय ↳ सब्सिडी की राशि को बढ़ाए जाए (very bad) ( पैसा नहीं एवं WTO का दबाव )

↳ अप्रत्यक्ष कर को कम किया जाए (संभव)
GST विकल्प

3 Note कर के 2 प्रकार होते हैं ↳ प्रत्यक्ष कर :- जो व्यक्ति सरकार को चुकाता है उसी पर जिस कर का बोझ पड़े
उदा.- आयकर एवं निगम कर

↳ अप्रत्यक्ष कर :- सरकार को चुकाता कोई और व्यक्ति है जबकि भार किसी और पर पड़ता है।

उदा.- Serice tax, Vat, उत्पादन कर, आयात शुल्क etc

समाधान - GST लागू किया जाए

Note: वर्तमान समय में विकसित देश अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर करते हैं

Scanned by CamScanner

Note : GDP, GNP, NDP व NNP का मूल्यांकन सदैव वित्तीय वर्ष के आधार पर किया जाता है। जितने समय में आर्थिक गतिविधियाँ निष्पादित की जाती है वह उस देश का वित्तीय वर्ष कहलाता है। ( नॉर्वे - 8 माह, अण्टार्कटिका - 2 माह, आइसलैण्ड - 4 माह )

→ भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि को कम करने के प्रयास किये जा रहे है।

→ भारत का वित्तीय वर्ष - 1 April से 31 मार्च

→ 1947 - 67 तक भारत का वित्तीय वर्ष - 1 may से 30 April।

→ भारत में कृषि वर्ष - 1 july से 30 june ( RBI का भी वित्तीय वर्ष )

राष्ट्रीय आय ( किसी देश की साधन लागत पर एक वित्तीय वर्ष में ह्रास को घटाकर प्राप्त सकल राष्ट्रीय उत्पादन ही, उस देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है

$$GNP_{FC} - \text{ह्रास} = NNP_{FC}$$ (राष्ट्रीय आय) (NCERT)

Note IMF व WB के अनुसार $NNP_{MC}$ उस देश की राष्ट्रीय आय होती है।

Note राष्ट्रीय आय की गणना में सदैव अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग को सम्मिलित किया जाता है ना कि मध्यवर्ती वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को

अंतिम वस्तुएँ एवं सेवाएँ - जो बाजार में उपयोग के लिए तैयार हो।

राष्ट्रीय आय से संबंधित तथ्यात्मक बिन्दु :-

→ भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादाभाई नौरोजी द्वारा 1868 में

पुस्तक - Poverty and Unbritish rule in India - (20 रू. प्रति वर्ष आय बताई)

→ वैज्ञानिक रीति से भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का मापन वर्ष 1931 में VKRV राव द्वारा।

Scanned by CamScanner

→ राष्ट्रीय आय का जन्मदाता - साइमन कुजनेट्स

→ वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, अध्यक्ष
↓
प्रशांत चन्द्र महालनोबिस

सदस्य → M.K. गाडगिल
→ VKRV राव

NOTE - भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना एवं द्वितीय औद्योगिक नीति (1956) महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इन्हें भारत में सांख्यिकीय का पिता कहा जाता है।

PCM बिस की भारत जन्मदिवस (29 june) को राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

→ भारत में राष्ट्रीय आय का मापन केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (CSO) (1951 में स्थापित) के द्वारा किया जाता है।

NOTE - CSO को आंकड़े NSSO (राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं सर्वे संगठन) के द्वारा प्रदान किये जाते थे परन्तु वर्तमान में CSO को आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकीय केन्द्र (स्थापना 2005-06) के द्वारा प्रदान किये जाते हैं।

NOTE - राष्ट्रीय आय की गणना स्थिर कीमतों एवं चालू कीमतों पर की जाती है। चालू कीमत चालू वर्ष के आधार पर होती है तथा स्थिर कीमतें आधार वर्ष के पर ली जाती है।

हाल ही में भारत का आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया गया है।

## राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ :

(1) उत्पादन विधि :- उत्पादन

राष्ट्रीय आय की इस विधि में उत्पादन एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।

(2) आय विधि :- इस विधि के अन्तर्गत उत्पादन के समस्त साधनों से प्राप्त आय (किराया, ब्याज, मजदूरी एवं लाभ) को जोड़ा जाता है।

(3) व्यय विधि : इस विधि में कुल व्यय एवं बचतों को जोड़ा जाता है।

भारत में आय एवं उत्पादन विधि द्वारा गणना की जाती है।

Note :- भारत में (3) विधि से राष्ट्रीय आय की गणना नहीं की जाती है क्योंकि CSO के लिए व्यय एवं बचतों का अनुमान लगाना आसान नहीं है।

## राष्ट्रीय आय से जुड़ी अन्य अवधारणाएँ

(1) प्रति व्यक्ति आय :- $\frac{\text{राष्ट्रीय आय}}{\text{कुल जनसंख्या}}$

Note भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य / केंद्रशासित प्रदेश

1) गोवा 2) दिल्ली 3) सिक्किम 4) चंडीगढ़ 5) पांडिचेरी / पुडुचेरी

Note सबसे कम 'बिहार'

Note प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रचलित दरों (चालू वर्ष) एवं स्थिर कीमतों (आधार वर्ष) पर की जाती है।

Scanned by CamScanner

(2) क्रय शक्ति क्षमता (Purchasing power parity)

इस अवधारणा में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर के आधार पर किसी देश की प्रचलित मुद्रा के द्वारा प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है।

Note: 2015-16 के अनुसार सर्वाधिक PPP वाले देश
1) अमेरिका
2) चीन
3) भारत
4) जापान

(क्रय शक्ति क्षमता — Purchasing Power parity)

(3) हिन्दू विकास दर :- 1950-80 तक भारत की औसत वृद्धि दर 3-3.5% तक थी जिसे योजना आयोग के पूर्व सदस्य प्रो॰ राजकृष्णन ने व्यंग्यात्मक रूप में हिन्दू विकास दर की संज्ञा दी।

## आर्थिक विकास :

अर्थव्यवस्था में होने वाला गुणात्मक परिवर्तन आर्थिक विकास कहलाता है। भारत में आर्थिक विकास के लिए 2007 से प्रयास किए गए हैं (2007 से पहले तक आर्थिक संवृद्धि = आर्थिक विकास)

आर्थिक विकास की अवस्थाएँ :-

(1) आर्थिक संवृद्धि : अर्थव्यवस्था में होने वाला संख्यात्मक परिवर्तन

(2) आर्थिक समावेशीकरण : वह आर्थिक संवृद्धि जिसमें समस्त लोगों को आर्थिक क्रियाओं में शामिल किया जाए।

(3) सशक्तिकरण : वह आर्थिक संवृद्धि जिससे लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके।

→ UNDP के अनुसार लोगों की निम्नलिखित आवश्यकताएँ निर्धारित की गयी हैं -

Scanned by CamScanner

→ पेयजल, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, सुरक्षा, ऊर्जा, बीमा, बैंक

(4) आर्थिक स्थिरता :- वह आर्थिक संवृद्धि जिससे लगातार आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(5) आर्थिक सम्पोषणियता :- वह संवृद्धि जिसमें तय मापदण्डों एवं गुणवत्ता के आधार पर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता हो।

Note योजना आयोग के अनुसार भारत वर्तमान में 'समावेशीकरण' की अवस्था से गुजर रहा है (2060 के अन्त तक सम्पोषणियता को प्राप्त कर लिया जाएगा)

आर्थिक विकास को मापने के सूचकांक (UNDP द्वारा निर्धारित किये गए)

1) मानव विकास सूचकांक (HUMAN development Index) HDI

→ इसे UNDP के द्वारा वर्ष 1990 में शुरू किया गया (PAK. अर्थशास्त्री महबूब-उल-हक द्वारा प्रतिपादित), (प्रो. अमर्त्य सेन का योगदान)

→ यह आर्थिक विकास सूचकांकों में सर्वाधिक चर्चित सूचकांक है जिसके माध्यम से किसी देश में हुए सामान्य आर्थिक परिवर्तन को पहचाना जाता है)

→ इस सूचकांक में निम्न 3 उपसूचकांकों की गणना की जाती है -

1) जीवन प्रत्याशा सूचकांक LEI ( life

→ इस सूचकांक में किसी देश के नागरिक की औसत आयु का आकलन किया जाता है यही औसत आयु जीवन प्रत्याशा कहलाती है।

India पुरुष - 67.3 वर्ष

महिला - 68.6 वर्ष

Scanned by CamScanner

**Note:** सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा JAPAN (83.6 वर्ष)

## 2) शिक्षा उपलब्धता सूचकांक (EAI)

→ इस सूचकांक का आधार शिक्षा को माना गया है जिसमें निम्न दो गतिविधियाँ शामिल होती हैं

1. स्कूल में प्रवेश की औसत आयु (4.2 वर्ष)
2. स्कूल में बिताए हुए वर्षों की संख्या (11.4 वर्ष)

] India

4.2 years

**NOTE** - यह सूचकांक UNESCO के द्वारा शुरू किया गया है।

## 3) सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक (PCI) →(PPP पर गणना)

क्रय शक्ति क्षमता / Purchasing Power Parity

→ इस सूचकांक को विश्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है जिसके अंतर्गत देश के नागरिकों की आय क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निकाली जाती है।

**NOTE**

$$HDI = \frac{1}{3}(LEI + EAI + PCI)$$

**NOTE** भारत की स्थिति :-

1990 = 0.369 निम्नतम विकास सूचकांक (0.510 से कम)

2013 = 0.550

2014 = 0.586 - 135वाँ स्थान

2015 = 0.609 - 130वाँ --"-- (0.510 – 0.698)

मध्यम मानव विकास सूचकांक वाले देश

HDI उच्च = 0.698 – 0.783

0.800 से अधिक

**NOTE** कुल 189 देशों को शामिल किया गया है।

सर्वाधिक - नॉर्वे, आस्ट्रेलिया (0.944)

कम - नाइजीरिया (0.57) 0.337

HDI के आधार :- ① दीर्घायु स्वस्थ जीवन :- जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ② ज्ञान तक पहुंच - शिक्षा ③ बेहतरीन जीवन के लिए संसाधन - प्रति व्यक्ति आय

* 2010 से 3 नए सूचकांक और शामिल किए गए हैं ① असमानता प्रभाव ② लिंग असमानता ③ बहुआयामी गरीबी सूचकांक

* राज्य → 0.454 के साथ 17वाँ स्थान (असम को मिलाकर 7 N-E राज्यों को (असम के अतिरिक्त) एक माना गया है

G.D.I.

2) लैंगिक विकास सूचकांक (Gender development Index)

→ इसे UNDP द्वारा 1995 में शुरू किया गया। United National Development Program

→ इस सूचकांक में आर्थिक गतिविधियों का महिलाओं के जीवन पर जो प्रभाव पड़ता है का आकलन किया जाता है।

(A) जीवन प्रत्याशा सूचकांक (L E I) < पुरुष / महिला

(B) शिक्षा -॥-

(C) गृह -॥-

यह मानव विकास सूचकांक से बेहतर सूचकांक है क्योंकि इस सूचकांक के द्वारा पुरूष व महिला दोनों के विकास की पृथक जानकारी प्राप्त होती है।

3) लैंगिक सशक्तिकरण सूचकांक :- (GEM)

→ इसे UNDP द्वारा 1995 में शुरू किया गया।

→ इसके अन्तर्गत किसी देश में महिलाओं को प्राप्त निम्न 3 अधिकारों के आधार पर महिलाओं की स्थिति का मापन किया जाता है।

(A) कानून बनाने का अधिकार :- चुनाव एवं चयन का अधिकार

(B) कानून लागू करने का अधिकार - नौकरशाही में भूमिका

(C) योजना से लाभान्वित होने का अधिकार - आर्थिक योजना में लाभार्थी होना।

Note:- भारत की स्थिति (A) 7.72%
(B) 20.3%
(C) 18%

Scanned by CamScanner

(4) लैंगिक बेहतरी सूचकांक (GWI) :-

- घरेलू
  - ↓ कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं होता है।
  - ↓ अतः सामाजिक सम्मान में कमी
- कामकाजी
  - ↓ वाणिज्यिक मूल्य होता है।
  - ↓ अतः सामाजिक प्रतिष्ठा / सम्मान अधिक

→ इस सूचकांक में महिला के वाणिज्यिक मूल्य की गणना की जाती है।

→ यह सूचकांक UNDP द्वारा 2010 में शुरू

→ भारत में कामकाजी महिला - 19.86%

(5) तकनीकी उपलब्धता सूचकांक :- (TAI)

→ यह UNDP के द्वारा वर्ष 2001 में शुरू।

← नेतृत्व देश / समान्य / गतिशील ग्रहण / सीमांत

→ इस सूचकांक में निम्न 4 उपसूचकांक शामिल होते हैं -

1) तकनीकी सृजन (TC)
2) नई तकनीक का उपयोग (DNT)
3) पुरानी तकनीक का उपयोग
4) मानव कुशलता (Human skills)

→ India - गतिशील ग्रहण कर्ता

Note सर्वाधिक TAI वाले देश Leader Country नेतृत्व देश

① Finland ② Jermany ③ Japan ④ USA ⑤ S. korea

Scanned by CamScanner

Note समित ग्रहणकर्ता — सोमालिया एवं पाकिस्तान

NOTE मानव कुशलता को बढ़ाने के लिए हाल ही में Skill India कार्यक्रम शुरू किया है।

(6) सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक (GNHI)

→ 1972 में भूटान के द्वारा शुरू किया गया।

→ यह सूचकांक विकास को खुशहाली के नजरिए से देखता है क्योंकि विकास तभी विकास माना जा सकता है जब वह खुशी प्रदान करे।

→ इस सूचकांक में निम्न भौतिक व अभौतिक सूचकांकों को शामिल किया जाता है

1) प्रति व्यक्ति आय ] भौतिक
2) सुशासन (भ्रष्टाचार एवं सरकार व जनता के मध्य विवाद) ] भौतिक

3) पर्यावरणीय संरक्षण ] अभौतिक
4) सांस्कृतिक प्रोत्साहन ] अभौतिक

→ भावनाओं के आधार पर मापन किया जाता है।

* इस सूचकांक को लेकर भारत का रूख स्पष्ट नहीं है।

Scanned by CamScanner

# BUDJET {बजट}

बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द BOUGETTEE से हुयी है जिसका अर्थ है - चमड़े का थैला (पर्स)
शाब्दिक अर्थों में खर्चों का पूर्वानुमान ही बजट कहलाता है क्योंकि सभी अर्थशास्त्री व्यय को ही जीवन का आधार मानते हैं।
इन्हीं खर्चों को संतुलित करने के लिए व्यक्ति आय के साधन जुटाता है तथा दोनों क्रियाओं को संतुलित करना ही बजटिंग कहलाता है।

बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :→

1. भारत में सर्वप्रथम 1860 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विल्सन के द्वारा बजट बनाया गया, जिन्हें भारत में बजट का जनक कहा जाता है।

2. 1944 में बॉम्बे प्लान में बजट की नयी अवधारणा को अपनाया गया (व्यय से आय को सन्तुलित करना) तत्पश्चात संविधान सभा ने भी इसी आधार को अपनाया तथा संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान बनाए गए (अनुच्छेद 202 - राज्यों का बजट)

3. भारत में आम बजट आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा बनाया जाता है जिसे फरवरी माह के अंतिम दिन संसद में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

4. बजट में 3 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं - विगत वर्ष, चालू वर्ष, अग्रिम वर्ष

5. भारत के प्रथम वित्त मंत्री - लियाकत अली (अंतरिम सरकार)

स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट - षणमुखम चेट्टी द्वारा 26-11-1947 पेश किया गया।

Scanned by CamScanner

# BUDJET {बजट}

बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द BOUGETTEE से हुयी है जिसका अर्थ है - चमड़े का थैला (पर्स)

शाब्दिक अर्थों में खर्चों का पूर्वानुमान ही बजट कहलाता है क्योंकि सभी अर्थशास्त्री व्यय को ही जीवन का आधार मानते हैं।

इन्हीं खर्चों को संतुलित करने के लिए व्यक्ति आय के साधन जुटाता है तथा दोनों क्रियाओं को संतुलित करना ही बजटिंग कहलाता है।

बजट से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य :→

1. भारत में सर्वप्रथम 1860 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेम्स विलसन के द्वारा बजट बनाया गया, जिन्हें भारत में बजट का जनक कहा जाता है।

2. 1944 में बॉम्बे प्लान में बजट की नयी अवधारणा को अपनाया गया (व्यय से आय को सन्तुलित करना) तत्पश्चात संविधान सभा ने भी इसी आधार को अपनाया तथा संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट संबंधी प्रावधान बनाए गए (अनुच्छेद 202 - राज्यों का बजट)

3. भारत में आम बजट आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा बनाया जाता है जिसे फरवरी माह के अंतिम दिन संसद में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

4. बजट में 3 वर्षों के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं - विगत वर्ष, चालू वर्ष, अग्रिम वर्ष

5. भारत के प्रथम वित्त मंत्री - लियाकत अली (अंतरिम सरकार)

स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट - षणमुखम चेट्टी द्वारा 26-11-1947 पेश किया गया।

Scanned by CamScanner

61

6. संविधान के लागू होने के पश्चात प्रथम बजट 1950 में जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया।

7. हिन्दी में प्रथम बजट C.D. देशमुख के द्वारा पेश किया गया (RBI के गवर्नर से वित्त मंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति)

8. सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्तमंत्री — मोरारजी देसाई (10) बार
(8 संपूर्ण (आम) बजट + 2 अंतरिम बजट)
दूसरे स्थान पर P. चिदम्बरम (8 आम बजट + 1 -II-)

9. भारत के वे वित्त मंत्री जो बाद में राष्ट्रपति बने — R. वेंकटरमन
— प्रणब मुखर्जी

10. —II— जो बाद में P.M. बने — डॉ. मोरारजी देसाई
— चौधरी चरण सिंह
— विश्वनाथ प्रताप सिंह
— डॉ. मनमोहन सिंह

11. भारत के वे P.M. जिन्होंने बजट पेश किया — पंडित Nehru (1958)
— इन्दिरा गांधी (1970)
— राजीव गांधी (1987)
— मनमोहन सिंह (2010 व 2012)

Scanned by CamScanner

भारत का आम बजट :→

"वार्षिक वित्तीय विवरण"
↑
अनु० -112

बजट (वार्षिक विवरण)

- आय पक्ष
  - (71%) राजस्व आय
    - कर से प्राप्त आय (63%)
      - 33% प्रत्यक्ष कर
        - निगम कर
        - आय कर
      - 30% अप्रत्यक्ष कर
        - → उत्पाद कर
        - → आयात शुल्क
        - → सेवा कर
    - गैर-कर से प्राप्त आय (8%)
      - → सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी से प्राप्त लाभांश
      - → जुर्माना व शुल्क
      - → अनुदान [WB, IMF]
      - → सार्वजनिक उधार
  - 29% पूंजीगत आय (ऐसी आय को वापस चुकाना होता है - ऋण, विनिवेश 26%, 3%)
- व्यय पक्ष

निष्कर्ष :→ (1.) राजस्व आय > पूंजीगत आय

(2.) कर से आय > गैर कर से आय

(3.) प्रत्यक्ष कर की आय > अप्रत्यक्ष कर की आय

(4.) निगम कर > आय कर

(5.) उत्पाद कर से आय > आयातकों से आय > सेवा कर से आय

व्यय पक्ष

- योजनागत व्यय
  ↓
  योजना के माध्यम से खर्च
  ↓
  सरकारी योजना, पंचवर्षीय योजना
- गैर योजनागत व्यय
  ↓
  आवश्यकता एवं सहायता के लिए
  ↓
  वे खर्च जो किसी योजना के आधार पर नहीं किए जाते हैं अपितु आवश्यकता एवं सहायता के लिए किये जाते हैं।

Scanned by CamScanner

योजनागत व्यय :→ सरकार के वे खर्च जो योजना के आधार एवं अन्तर्गत किए जाते हैं। (पंचवर्षीय योजना एवं सरकारी योजना के अन्तर्गत किए गए खर्च)

इसमें निम्नलिखित दो व्यवहार सम्मिलित होते हैं –

1) ऋण अदायगी

2) निवेश (विकास के लिए किया गया खर्च)

गैर योजनागत व्यय :→ इसमें भी तीन व्यवहार शामिल होते हैं –

1) ब्याज की अदायगी
2) सब्सिडी
3) रक्षा
4) वेतन, पेंशन

व्यय पक्ष 1978060 करोड़ —
- केन्द्र का हिस्सा 63% (65)
- राज्यों का हिस्सा 37 (35)

NOTE: 1) सर्वाधिक खर्च ब्याज चुकाने में। फिर सब्सिडी तथा बाद में रक्षा पर खर्च।

2) गैर योजनागत व्यय > योजनागत व्यय

NOTE: अगले वर्ष में सब्सिडी में 3% कटौती का लक्ष्य रखा गया है।

3) कुल व्यय > कुल आय

घाटा = 5,33,904 करोड़

↓

भारत का कुल घाटा (राजकोषीय घाटा) GDP के 3.5% के बराबर है। 2014-15 में घाटा 4.5% रहा। 2015-16 ⇒ 3.62, 2016-17 → 3.62% अनुमान है,

– राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम – 2005 (F.R.B.M.A) के अनुसार राजकोषीय घाटा GDP के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए।

## * बजट में घाटे के प्रकार :→

1) बजटीय घाटा : वर्तमान में यह राजकोषीय घाटा कहलाता है।

(कुल व्यय – कुल आय) अर्थात् सरकार की देनदारियाँ ही राजकोषीय घाटा है।

→ इस घाटे को दूर करने के उपाय :- 1. नए नोटों का निर्गमन (Bad idea)
↓
वर्ष 1997 तक बजटीय घाटे को दूर करने के लिए सरकार नए नोटों के निर्गमन से संतुलन बनाती थी परन्तु इस उपाय की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इससे मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती थी जिससे मांग बढ़ जाती थी तथा साथ ही मुद्रा स्फीति में वृद्धि होती थी।

अत: 1997 के पश्चात डॉ. मनमोहन सिंह ने इस घाटे को दूर करने के लिए निम्न उपाय बताए –

1. बजटीय घाटे की जगह राजकोषीय घाटा
2. घाटे को दूर करने के लिए सरकार ऋण एवं निवेश को बढ़ावा दे।

* अन्य उपाय : →
1. कर की दरों में वृद्धि (कुर्सी का खतरा)
2. सब्सिडी में कमी (सम्भव नहीं) कनिष्ठ रूप को लें DBT ले
3. कर में सुधार (BEST- GST)
4. तकनीकी एवं कुशलता का विकास (जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन हो)
(GDP ++) (skill india, Digital India)

**NOTE** राजकोषीय घाटा कभी भी GDP के 3% से अधिक नहीं होना चाहिए F.R.B.M.A 2003

**NOTE** 2012-13 में यह घाटा GDP के 4.8% तक था। जिसे प्रतिवर्ष 0.3 तक कम करने का लक्ष्य रखा गया।

2. **राजस्व घाटा** :=> ~~राजस्व आय~~ -

राजस्व व्यय - राजस्व आय

राजस्व व्यय ↓ गैर योजनागत व्यय

राजस्व आय ↓
- → प्रत्यक्ष कर
- → अप्रत्यक्ष कर
- → गैर कर से प्राप्त आय

→ 2003 में लक्ष्य रखा गया कि राजस्व घाटा = GDP का 0% होना चाहिए क्योंकि राजस्व घाटा बताता है कि सरकार के पास दैनिक कार्यों को पूरा करने के भी पैसे नहीं है। वर्तमान में यह GDP के 2.3% के बराबर है। (पिछले वर्ष GDP का 2.5% था) [illegible] 2015-16 [illegible] 231 [illegible]

→ रोकने का उपाय → राजस्व आय में वृद्धि (करों में सुधार)

3. **प्राथमिक घाटा** :=> प्राथमिक व्यय - प्राथमिक आय

प्राथमिक व्यय ↓ समा॰ कल्याण एवं विकास पर खर्च

प्राथमिक आय ↓ ऋण को छोड़कर अन्य आय

→ वर्तमान में प्राथमिक घाटा GDP का .3% है। (निरन्तर कमी हो रही है।)

4. **प्रभावी राजस्व घाटा** :=> राजस्व घाटा - राज्यों पर किया गया व्यय

→ सरकार के द्वारा राज्यों पर किया गया खर्च ही प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है।

Scanned by CamScanner

66

- बजट के प्रकार : =>

1.) गद क्रम बजट (Line Item Budget)

→ इसे परम्परागत बजट भी कहते हैं।

→ ऐसे बजट में खर्च पर जोर दिया जाता है ना कि खर्च के उद्देश्य पर

2.) निष्पादन बजट (Performance Budget)

→ वह बजट जो खर्च के उद्देश्यों पर जोर देता है।

→ भारत मे इस बजट की शुरूआत सर्वप्रथम 1987 में राजीव गांधी के द्वारा की गयी।

3.) शून्य आधारित बजट (Zero based Budgeting)

→ इस बजट में पुरानी मदों को शून्य कर दिया जाता है तथा नए सिरे से बजट बनाया जाता है।

→ इस बजट की शुरूआत 1960 के दशक में जिमी कार्टर (जॉर्जिया के गवर्नर, USA) के द्वारा की गयी

NOTE: 2014-15 का मनरेगा बजट इसी आधार पर बनाया गया।

4.) परिणाम आधारित बजट (Outcome Budget)

→ 2005 में पी. चिदम्बरम

→ ऐसा बजट जिसमें परिणाम के आधारित व्यय किया जाता है तथा जिसकी निरन्तर समीक्षा की जाती है।

Scanned by CamScanner

67

5.) अन्तरिम बजट :=> (Interim Budget)

→ चुनावी वर्ष में नीतिगत निर्णय लेने हेतु बनाया गया बजट।

→ इसे संपूर्ण वर्ष के लिए नहीं बनाया जाता।

6.) जेण्डर बजट :=>

→ 2005 पी. चिदम्बरम

→ वह बजट जिसमें महिलाओं के लिए अलग से खर्च की व्यवस्था की जाती है ताकि आर्थिक क्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़े।

Scanned by CamScanner

# ☆ भुगतान - संतुलन ☆
## { Balance of Payment }

* वर्तमान वैश्वीकरण के युग मे प्रत्येक देश अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन के माध्यम से अपना आर्थिक विकास करना चाहता है। इसी सन्दर्भ में उस देश को विदेशों से आयात भी करना होता है तथा माथ निर्यात भी किया जाता है। इन दोनों व्यवहारों में रखा गया सन्तुलन ही भुगतान सन्तुलन कहलाता है। (निर्यात-आयात में रखा गया सन्तुलन)

* भुगतान सन्तुलन में निम्नलिखित 2 व्यवहार शामिल होते हैं।

व्यवहार
- अल्पकालीन व्यवहार (1 वर्ष तक)
  - चालू खाते के व्यवहार
    - आयात
      - दृश्य मदों का
        - तेल कच्चा
        - सोना
      - अदृश्य मदों का
    - निर्यात
      - दृश्य मदों का
      - अदृश्य मदों का
- दीर्घकालीन व्यवहार
  - पूंजीगत खाते के व्यवहार
    - विदेशी ऋण
    - विदेशी निवेश

* चालू खाते के व्यवहार :⇒ 1) दृश्य मदों के व्यवहार
  - → ऐसे व्यवहार जिन्हें आँखो से देखा जा सके तथा जिन्हे बंदरगाह पर रिकॉर्ड किया जा सके अर्थात वस्तुओं के व्यवहार।
  - → इसे व्यापार खाता भी कहते हैं।

  इस खाते / व्यवहार में निम्न दो दशाएँ पायी जा सकती है —

Scanned by CamScanner

1. आयात > निर्यात (घाटा)
2. निर्यात > आयात (आधिक्य)

NOTE: भारत में इस व्यवहार में घाटे की स्थिति है। इस घाटे को व्यापार घाटा कहा जाता है।

→ व्यापार घाटे के कारण :→ 1.) POL वस्तुओं का अधिक आयात
↓
पेट्रोल, ऑयल, स्नेहक
2.) सोने की अधिक माँग

→ निवारण :- 1.) सोने की खपत को कम किया जाए
2.) सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए।
3.) डीजल एवं पेट्रोल के सहउत्पादों को बढ़ाया जाए।

वर्तमान सरकार के सोने की खपत को कम करने के उपाय :- भारत में आम नागरिक सोने के उपभोग के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश भी करते हैं।

→ निवेशकों को सोने के मूल्य के उतार-चढ़ाव से फर्क पड़ता है अतः ऐसे निवेश के लिए वर्तमान सरकार ने निम्नलिखित 2 योजनाएँ शुरू की हैं –

(1.) सम्प्रभु गॉल्ड बॉन्ड योजना :→ ① केन्द्र सरकार द्वारा 8 वर्ष की अवधि तक गॉल्ड बॉन्ड जारी किए जाएगें।

② ऐसे बॉन्डों की नीलामी RBI के द्वारा की जाएगी तथा प्राप्त रकम केन्द्र सरकार को दी जाएगी।

③ min सोना = 2 gm. व max. सोना = 500 gm. प्रति निवेशक

Scanned by CamScanner

70

④ निवेशक bank एवं Post office के माध्यम से ऐसे bond खरीद सकते हैं।

⑤ ब्याज की दर = 2.75% अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
(निवेशकों को यदि लाभ होता है तो उस पर कर नहीं लगाया जाएगा)

⑥ निवेशक 5 वें वर्ष में प्रपत्र (bond) को बेचकर अपना निवेश प्राप्त कर सकता है उससे पहले नहीं प्राप्त कर सकता।

(2.) गोल्ड मौद्रिकीकरण योजना :→ ① इस योजना के अन्तर्गत नागरिक अपना भौतिक सोना अथवा आभूषण बैंकों के पास जमा करा सकते हैं
(min. 30 gm. सोना, अधिकतम कोई सीमा नहीं)

② जमा किए गए सोने की कीमत के बराबर रकम जमाकर्ता के गोल्ड बचत खाते में जमा कर दी जाएगी।

③ निवेश की वैधता अवधि :→ min. 1 साल, max. 15 साल

④ निवेश पर ब्याज की दर → 2-2.5% वार्षिक

⑤ वैधता अवधि के पश्चात् निवेशक या तो सोना प्राप्त कर सकता है या निवेश की रकम

NOTE पूंजीगत मशीनी उत्पादों में आयात को कम करने हेतु राष्ट्रीय पूंजीगत उत्पादक योजना April 2016 से शुरू की गयी जिसका लक्ष्य है कि 2025 तक भारत में पूंजीगत उत्पादों का उत्पादन 7-15 करोड़ टन किया जाए।

Scanned by CamScanner

71

अदृश्य मदों का व्यवहार :- ऐसे व्यवहार जो आँखों से दिखाई न दे तथा जिन्हें बंदरगाह पर दर्ज न किया जा सके

जैसे : सेवाओं के व्यवहार

NOTE भारत की स्थिति : निर्यात > आयात (आधिक्य)

NOTE अदृश्य व्यवहारों में आधिक्य का कारण :-

① भारत में सेवाओं के प्रति कम जागरूकता

② भारत का उत्तम सॉफ्टवेयर क्षेत्र

③ BPO व KPO सेवा

④ पर्यटन क्षेत्र

NOTE अदृश्य मदों का आधिक्य व्यापार घाटे से काफी कम है। इन दोनों का कुल सन्तुलन ही भारत का चालू खाते का घाटा कहलाता है।

NOTE राजकोषीय घाटा घरेलू मुद्रा के घाटे को दर्शाता है। तथा चालू खाते का घाटा, विदेशी मुद्रा के घाटे को दर्शाता है तथा ये दोनों घाटे आपस में जुड़कर जुड़वा घाटे कहलाते हैं।

NOTE भारत में चालू खाते का घाटा वर्तमान में GDP का ~~2.3~~ 1.5 % है।

NOTE विगत 3 महीनों में भारत के कुल आयातों में 16% की कमी आयी है। (कच्चे तेल की कीमतों में कमी)

↓ के कारण

① यूरोपियन संघ की आर्थिक वृद्धि में कमी जिससे कच्चे तेल के आयात में कमी।

② चीन संकट ③ अमेरिका द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति को बढ़ाना

Scanned by CamScanner

**पूंजीगत खाता:** दीर्घकालीन प्रकृति के व्यवहार
(1 साल से अधिक)

## विदेशी ऋण

1. चालू खाते के घाटे की पूर्ति → अल्पकालीन IMF करने हेतु एवं बुनियादी ढाँचे को → दीर्घकालीन IBRD मजबूत करने हेतु भारतीय सरकार विदेशी आर्थिक संगठनों से ऋण प्राप्त करती है जिसे विदेशी ऋण कहा जाता है।

2. यह विदेशी ऋण IMF, WB, ADB, BRICS BANK इत्यादि से लिया जाता है।

3. विदेशी ऋण अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रकृति का होता है।

(17% अल्पकालीन IMF
83% दीर्घकालीन) IBRD

**NOTE** भारत का कुल विदेशी ऋण 480 बिलियन डॉलर है।

$10^6$ = मिलियन (दस लाख)

$10^9$ = बिलियन (अरब)

$10^{12}$ = ट्रिलियन (दस खरब)

एवं विदेशी मुद्रा भण्डार
→ 362 बिलियन डॉलर

## विदेशी निवेश

FDI | FII

विदेशी नागरिकों एवं संस्थाओं द्वारा भारत में किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है।
यह निम्नलिखित दो माध्यमों से किया जाता है –

① **FDI**: (Foreign direct investment)
(विदेशी प्रत्यक्ष निवेश)
→ यह स्थायी प्रकृति का निवेश होता है जिसमें प्रबंधन में विदेशियों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है।
(min. 10%
max. 100%)

**NOTE** FDI में पूंजी पलायन की प्रवृत्ति कम होती है।

② **FII** (Foreign Institutional investment)
(विदेशी संस्थागत निवेश)
→ यह अस्थायी प्रकृति का निवेश होता है जिसमें विदेशी संस्थाएँ बिना प्रबंधन में भागीदारी लिए भारतीय बाजार में निवेश करती हैं।

Scanned by CamScanner

अतः भारत का विदेशी ऋण विदेशी मुद्रा के भण्डार की तुलना में बहुत अधिक है, जिसे दूर करने के लिए विदेशी निवेश की आवश्यकता होती है।

→ FII में पूंजी पलायन की प्रवृत्ति अधिक पायी जाती है। अतः इन्हें Hot Money कहा जाता है।

NOTE: FDI व FII में अन्तर के लिए अरविन्द मायाराम समिति का गठन किया गया (2011 में) तथा FII की व्याख्या के लिए चन्द्रशेखर समिति का गठन किया गया। (2009 में)

* भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य :-

① भारत के प्रमुख निर्यातक उत्पाद एवं सेवाएँ :→ "सॉफ्टवेयर, कृषि उत्पाद, चमड़ा, जेम्स & ज्वेलरी, हस्तशिल्प एवं वस्त्र (रत्न)

② —"— निर्यातक देश :→ यूरोपियन संघ (EU)
UAE
USA
CHINA
Singapur

③ —"— आयातक उत्पाद → कच्चा तेल, सोना, पूंजीगत उत्पाद (जो लम्बे समय तक काम आए), मशीनरी, रसायन

Scanned by CamScanner

स्वास्थ्य शिक्षा व कृषि कल्याण CESS
NOTE:

④ प्रमुख आयातक देश → China
UAE
Switzerland
USA
Singapur

⑤ भारत के कुल निर्यात → 477.1 बिलियन डॉलर I
दृश्य मदों के निर्यात → 321.5 -॥- II
अदृश्य -॥- → 155.6 -॥- III

⑥ भारत के कुल आयात → 609.9 -॥- IV
दृश्य -॥- → 463 V
अदृश्य -॥- → 146.9 VI

→ व्यापार घाटा = V - II (दृश्य मदों के कुल आयात - निर्यात)
अदृश्य मदों का आधिक्य = VI - III (+) (अदृश्य मदों का कुल आयात - निर्यात)
चालू खाते का शेष = IV - I (-) (कुल आयात - कुल निर्यात)

* भुगतान सन्तुलन को व्यवस्थित करने के उपाय :->

**राजकोषीय उपाय**

आयातों को कम व निर्यातों को अधिक करने के सरकारी उपाय

सरकार द्वारा

**मौद्रिक उपाय**

आयात - - - कम करो

निर्यात + + + + अधिक

RBI के द्वारा

(A) आयातों को कम करने के सरकारी उपाय

→ आयात प्रतिबन्ध नीति (1950 - 1991)

→ आयात प्रतिस्थापन नीति

(B) निर्यात को बढ़ावा देने के सरकारी उपाय

(I) निर्यात संवर्द्धन नीति

→ सब्सिडी

→ SEZ की स्थापना (special economic Zone)

(II) निर्यात ब्रांडिंग नीति

>>> Focus Market

↓

लैटिन अमेरिका, ASEAN, West Asia, South asia

>>> Focus Product

↓

Gems & Jewelleries, पर्यटन, Software

Scanned by CamScanner

भुगतान सन्तुलन को व्यवस्थित करने के मौद्रिक उपाय :→ भुगतान सन्तुलन को व्यवस्थित रखने के लिए RBI के द्वारा आयात को कम करने एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन्हें मौद्रिक उपाय कहते हैं।

इसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं –

(1) मुद्रा की तरलता में कमी करने के उपाय :- CRR, SLR, RR

(2) रूपए का अवमूल्यन :- जब सरकारी प्रयासों से भारतीय मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर दी जाए तो इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं।

यदि ऐसा उपाय अपनाया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा की क्रयशक्ति में कमी आ जाती है जिससे निर्यातकों को लाभ पहुँचता है तथा आयातकों को नुकसान।

चूंकि भारत में निर्यात < आयात, अतः यह उपाय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक नहीं माना गया है।

NOTE स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत में 1949, 1968 एवं 1991 में रूपए का अवमूल्यन किया जा चुका है।

Scanned by CamScanner

71.

# सब्सिडी एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

सब्सिडी ↓ का अर्थ है 'सहायता' जो आर्थिक रूप में की जाए।

सामान्यतया इसे सम्प्रभुता की कीमत कहा जाता है जो निम्न उद्देश्यों के लिए चुकायी जाती है -

1.> सामाजिक न्याय के लिए
2.> मुद्रा स्फीति एवं अवस्फीति की दशा से निपटने के लिए
3.> आर्थिक प्रेरणा के लिए

## सब्सिडी के प्रकार :-

1) स्वरूप के आधार पर :-

(A) प्रत्यक्ष सब्सिडी :→ जिसका उल्लेख बजट में किया जाता है।

(B) अप्रत्यक्ष सब्सिडी :→ —"— नहीं —"—

निष्कर्ष → अप्रत्यक्ष सब्सिडी (60%) > प्रत्यक्ष सब्सिडी (40%)

2) प्रभाव के आधार पर :-

(A) मेरिट सब्सिडी → वह सब्सिडी, जिसका प्रभाव समाज के व्यापक वर्ग पर पड़ता हो।
जैसे : शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस etc.

(B) गैर मेरिट → जिसका व्यापक प्रभाव ना पड़ता हो।
→ जो कुछ वर्ग के लिए घोषित हो।
Ex. Petrol, deisel & Gas पर दी जाने वाली सहायता

3) क्षेत्र के आधार पर :-

(A) आर्थिक सब्सिडी :→ अर्थव्यवस्था के विस्तार के उद्देश्य से दी गयी आर्थिक सहायता।
जैसे > आधारभूत संरचना के लिए दी गयी सहायता

(B) सामाजिक सब्सिडी :→ सामाजिक न्याय एवं कल्याण के लिए दी गयी सहायता

जैसे :- गरीब महिलाओं एवं बच्चों को दी गयी सहायता।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए दी गयी सहायता।

4) खाद्यान्नों के आधार पर दी गयी सब्सिडी

(A) खाद्य सब्सिडी :→ जो खाद्य प्रबन्धन के लिए दी जाए।

* खाद्य प्रबन्धन :→

खाद्य प्रबंधन → सब्सिडी → खाद्य सब्सिडी

- खाद्य उत्पादन
  - MSP - 1986 (न्यूनतम समर्थित मूल्य)
  - यूरिया
  - उर्वरक, सिंचाई
  - बीज पर सहायता
- खाद्य भण्डारण एवं प्रसंस्करण
  - CWC 1957
  - SWC 1957
  - FCI 1965
- खाद्य वितरण
  - PDS 1966
  - 1996 - उचित मूल्य की दुकानें (लक्ष्य आधारित (1997))
  - 2000 - अन्त्योदय
  - 2013 - खाद्य सुरक्षा अधिनियम

1) खाद्य उत्पादन :→ खाद्य प्रबंधन में सबसे प्रमुख क्रिया खाद्य उत्पादन मानी गयी है क्योंकि बिना उत्पादन के ना भण्डारण संभव है और ना ही वितरण। अतः सरकार खाद्य उत्पादकों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार की सहायता देती है। जैसे - खाद्य व बीज पर दी गयी सहायता
- सिंचाई -"-
- न्यूनतम समर्थित मूल्य के रूप में सहायता

Scanned by CamScanner

71

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) : भारत में MSP की शुरुआत 1966 में की गयी जिसके अन्तर्गत सरकार न्यूनतम मूल्य पर किसानों से खाद्यान्नों को खरीदती है ताकि किसानों को उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाए तथा बाजार में दाम गिरने पर भी खाद्यान्नों के लिए न्यूनतम मूल्य की सुरक्षा रूपी दी जा सके।

NOTE : भारत में MSP की घोषणा खाद्यान्नों की बुवाई से पहले की जाती है।
(खरीफ - जून ; रबी - नवम्बर)

NOTE : MSP की घोषणा के लिए कोई मंत्रालय नहीं है। भारत में इसकी घोषणा 'कृषि लागत एवं मूल्य आयोग' (CACP) के द्वारा की जाती है।
(स्थापना - 1985)
↓
Comission for Agri cost & price

→ 1985 से पहले MSP की घोषणा कृषि मूल्य आयोग के द्वारा की जाती थी।

NOTE : MSP केवल खाद्यान्नों के लिए जारी किया जाता है। (कुल 21 खाद्यान्न फसलें)

[ धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, जौं, चना, अरहर, मूंग, उड़द, तूड़ (तूअर), नारियल, जूट, कपास, गन्ना, तम्बाकू, मोटे अनाज, कच्ची दाल, सरसों, सोयाबीन ]

→ प्रमुख खाद्यान्न फसलों को 3 भागों में बांटा गया है – अनाज
– दाल
– तिलहन

→ MSP के जैसे ही राज्य सरकार भी अपने राज्य के किसानों के लिए राज्य प्रशासित मूल्य की घोषणा करती है। इसी मूल्य को लेकर 2014 में U.P में
(SAP)
चीनी मिल के मालिकों एवं सरकार (U.P) के मध्य विवाद बढ़ गया था।
(गन्ने के SAP को दुगुना कर दिया गया था।)

Scanned by CamScanner

चीनी मिल के मालिकों को वित्तीय सहायता देने के लिए SEFASU योजना 2011 में शुरू की गयी।

↓

चीनी इकाईयों की वित्तीय सहायता योजना

[Scheme for extending financial assistance for Sugar Undertaking]

इस योजना में चीनी मिल के मालिकों को 6600 करोड़ की वित्तीय सहायता सस्ते ऋण के रूप में प्रदान की गयी है।

खाद्य भण्डारण एवं प्रसंस्करण :⇒ भारत में भण्डारण की समस्या एक गंभीर समस्या है क्योंकि भारत के भण्डारण में आधुनिकता का अभाव है जिसके चलते उत्पादन का बहुत अधिक भाग नष्ट हो जाता है। फलस्वरूप मांग एवं पूर्ति में असंतुलन हो जाता है तथा मुद्रा स्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पारित किया गया तथा भारत सरकार को कृषि उत्पाद के भण्डारण, कीमत निर्धारण व इसे नियमन करने की शक्ति प्राप्त हुई।

इसी सन्दर्भ में भण्डारण की सुविधा कम कीमत पर उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय गोदामीकरण संस्था की स्थापना की गई तथा राज्यों में राज्य गोदाम की स्थापना (1957) की गयी।

CWC एवं SWC के साथ खाद्यान्नों के वैज्ञानिक रीति से भण्डारण के लिए भारतीय खाद्य निगम (FCI) की स्थापना वर्ष 1965 में की गयी। यह संस्था सरकार के द्वारा घोषित MSP पर किसानों से खाद्यान्नों को खरीदती है तथा लम्बे समय तक खाद्यान्नों को उपयोगी बनाने के लिए वैज्ञानिक रीति से भण्डारण का कार्य करती है।

Note: भण्डारण एवं प्रसंस्करण की सुविधा को अत्याधुनिक बनाने के लिए 2007 में WDRA (Warehousing development & Regulatory Authority) (गोदामीकरण विकास एवं नियामक संस्था) की स्थापना की गयी जो वर्तमान में निम्न तकनीकों के माध्यम से प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है –

1. जैविक तकनीक :- खाद्यान्नों के लिए
2. नैनो तकनीक :- प्याज, टमाटर एवं मसाले।

3) खाद्य वितरण :⇒ खाद्य वितरण के लिए भारत में 1960 के दशक में Pds को अपनाया गया। जिसमें सरकार के द्वारा घोषित योजनाओं का लाभ वंचित वर्गों तक एक चैनल के माध्यम से लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया।

इस व्यवस्था में मौजूद मध्यस्थों में व्याप्त भ्रष्टाचार की वजह से योजनाओं का सम्पूर्ण लाभ वंचित वर्ग तक नहीं पहुँच पा रहा था अतः 1997 में लक्ष्य आधारित Pds (TPds) को अपनाया गया तथा उचित मूल्य की दुकानें स्थापित की गयी जो प्रत्यक्षतः वंचित वर्गों को कम कीमत पर अनिवार्य वस्तुएँ उपलब्ध करवाने के लिए खोली गयी।

इस व्यवस्था में वंचित वर्गों को दो वर्गों में बाँटा गया -

1. APL (गरीबी रेखा से ठीक ऊपर) :- ऐसे वर्गों को सामान्य आर्थिक कीमतों पर अनिवार्य वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती है।

2. BPL (-॥- नीचे) :- APL से आधी कीमतों पर अनिवार्य वस्तुएँ उपलब्ध करायी जाती है।

**Note**:- वर्ष 2000 में इस प्रणाली में एक नया वर्ग जोड़ा गया

→ अन्त्योदय (गरीबों में गरीब) :- ऐसे वर्गों को सरकार 2/kg गेंहू तथा 3/kg र चे चावल उपलब्ध कराती है।

**NOTE**:- अन्त्योदय योजना में APL वर्गों के लिए 25 kg. खाद्यान्न प्रतिमाह प्रतिपरिवार तथा BPL वर्गों के लिए 35 kg. खाद्यान्न प्रतिमाह

Scanned by CamScanner

NOTE :- अन्त्योदय योजना में अन्त्योदय वर्ग को BPL में शामिल किया गया है।

→ भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम Sept. 201 को लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार वंचित वर्गों (BPL एवं अन्त्योदय) को 3 ₹/kg चावल, 2 ₹/kg गेहूं व 1 ₹/kg मोटा अनाज उपलब्ध कराती है।

राज. में 2 oct. 2013 को यह योजना नागौर जिले से शुरू की गयी।

→ मिड-डे-मील योजना को मिला दिया गया।

→ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत सरकार प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को 450 cal. भोजन एवं 12 gm. प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराती है। (उच्च प्राथमिक के लिए 750 cal एवं 26 gm. प्रोटीन युक्त भोजन)

Scanned by CamScanner

# ☆ भारत में कर - प्रणाली ☆

**कर** :- किसी नागरिक के द्वारा सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान, जिसमें भुगतान करने वाले व्यक्ति को कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है। (सामान्य)

भारत के संविधान के अनुच्छेद- 39 में संसाधनों के सबके हितों में उपयोग की बात कही गयी है तथा अनुच्छेद -46 समाज के कमजोर वर्ग के हितों के उपयोग के प्रावधान बताता है। ऐसा तभी सम्भव है जब कुछ लोगों से संसाधन वसूल किया जाए तथा उसे कमजोर वर्गों में बांटा जाए। इसी उद्देश्य के लिए भारतीय संविधान, सरकार को कर लगाने की गर्भित शक्ति प्रदान करती है।

**कर - प्रणाली के प्रकार :→**

(1.) प्रगतिशील कर-प्रणाली :→ जब आय बढ़ने के साथ- साथ कर की दर भी बढ़े। (भारत में यही कर प्रणाली है।)

(2.) प्रगतिहीन कर - प्रणाली :→ vice versa of Above आय ↑ कर ↓
(प्रतिगामी)
→ भारत में इसी प्रणाली की मांग चल रही है।

(3.) आनुपातिक कर -प्रणाली :→ सभी के लिए कर की दर समान हो।
→ भारत में service- Tax (सेवा कर) इसी कर प्रणाली का उदाहरण है।

**भारत में करों के प्रकार :→**

(1.) प्रत्यक्ष कर (हटा दिया) :- वह कर जो किसी व्यक्ति अथवा संस्था पर लगाया जाता हो तथा जिसे हस्तांतरित नहीं कर सकते हों। e.g. आयकर, निगम कर, Present सम्पति कर, उपहार कर

पी. निष्कर्ष [ FBT सुविधाओं पर
MAT न्यूनतम वैकल्पिक कर

(2.) अप्रत्यक्ष कर : वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाला कर।
→ ऐसे कर को हस्तांतरित कर सकते हैं।

Scanned by CamScanner

## भारत के प्रमुख प्रत्यक्ष कर :-

1. आयकर ( Income Tax ) :-

↳ व्यक्तिगत आय अथवा हिन्दू अविभाजित परिवार की आय पर लगने वाला कर, आयकर कहलाता है।

↳ भारत में इसकी शुरूआत 1860 में की गयी। वर्तमान में आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत आयकर लगाया जाता है। वर्तमान आय पर, भूतकालीन आय पर, भावी आय पर।

↳ आयकर अधिनियम में वर्तमान बजट में करदाता को निम्न तीन श्रेणियों में बांटा गया है –

(i) 60 वर्ष तक की आयु के करदाता

(ii) ~~>60 परन्तु~~ 60 से अधिक परन्तु 80 आयु से कम करदाता (वरिष्ठ नागरिक)

(iii) 80 से अधिक ( सुपर वरिष्ठ नागरिक )

→ 60 वर्ष तक की आयु(i) – करमुक्त आय , 2,50,000 ₹

(ii) 3,00,000

(iii) 3,00,000

→ आयकर अधिनियम की धारा 87 B में छूट की सीमा 2000 से बढ़कर 5000 ₹ कर दी गयी ( 5 लाख रू तक वाले व्यक्ति को )

NOTE प्रत्यक्ष कर संहिता ( DTC code ) के ~~अर्न्तगत~~ अंतर्गत सुपर वरिष्ठ नागरिकों की 5 लाख ₹ तक की आय को कर मुक्त रखने का प्रस्ताव ( बजट में था, संशोधित पर लागू नहीं )

85

2. निगम कर :→ कम्पनी (घरेलू), अन्य पंजीकृत संस्थाओं की आय पर लगने वाला कर, निगम कर कहलाता है।

→ वर्तमान में इस कर की दर 30% है।

NOTE DTC के प्रस्ताव के अनुसार निगम कर पर किसी भी प्रकार का उपकर (cess) अथवा अधिभार (surcharge) ना लगाया जाए।

NOTE ① उपकर (cess) :→ किसी विशेष प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा कर के साथ लिया गया कर।

→ यह प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जा सकता है।

वर्तमान :-
① स्वच्छ भारत अभियान 0.5
② कृषि कल्याण कर 0.5

② अधिभार (surcharge) → चुकाए गये कर के ऊपर कर लगाना

→ यह कर केवल प्रत्यक्ष करों पर ही लगाया जा सकता है।

→ दोनों ही कर संघ सूची के विषय हैं। अतः इनसे प्राप्त आय को राज्यों के साथ नहीं बाँटा जाता है।

NOTE 1 june 2016 से .5 प्रतिशत की दर से कृषि कल्याण cess लगाया जा चुका है।

3. न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) minimum alternative Tax

↳ यह कर घरेलू कम्पनियों की आय पर लगाया जाता है।

NOTE 2005 के बजट से विदेशी कम्पनियों की आय पर भी MAT लागू अनिवार्य कर दिया गया है।

वर्तमान में इस कर की दर = 18.5% (DTC के प्रस्तावों के अनुसार यह दर 17.5% रखी गयी थी)

NOTE 2006 से हर प्रकार की गतिविधि को कर के दायरे में शामिल करने हेतु निम्न चार प्रकार के कर तत्कालीन वित्तमंत्री P. चिदम्बरम के द्वारा लागू किए गए –

Scanned by CamScanner

81

(i) B.T.T. (Banking Transaction Tax) :- बैंकों के साथ किए गए रोकड़ के व्यापार पर लगाया गया टैक्स (हटा दिया) बैंकिंग व्यवहार (सफेद धन) को प्रोत्साहन देने हेतु

(ii) FBT (Frindge benefit tax) :- सुविधाओं पर लगाया गया कर
(2009 में समाप्त)
(2005 में लागू)

(iii) STT (प्रतिभूति के व्यवहार पर लगने वाला कर) (.001 %)

(iv) वायदा बाजार में होने वाले व्यवहारों पर लगाया गया कर - CTT (commodity)
ऐसी वस्तुएँ जिनके मूल्य काफी उतार-चढ़ाव होता है

NOTE: वर्तमान में CTT एवं STT कर लगता है। अपति वापस नहीं लिया गया।

अप्रत्यक्ष कर :→

1. उत्पाद कर (Excise Duty) :→ उत्पादन पर लगने वाला कर

2. आयात शुल्क (Custom Duty) :→ आयातित वस्तुओं पर लगने वाला कर

3. सेवा कर :→ सेवाओं पर लगने वाला कर

सेवा कर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें : ① मूल संविधान में सेवा कर की व्यवस्था नहीं की गयी है परन्तु 1994 में अनु. 248 का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार के द्वारा निम्न तीन सेवाओं पर सेवाशुल्क लगाया गया -
(i) हवाई यात्रा
(ii) टेलि टेलीफोन
(iii) शेयर व्यापार की सुविधा

Scanned by CamScanner

(2) अनु. 248 के अन्तर्गत कोई भी गतिविधि बहुत लम्बे समय तक नहीं चलायी जा सकती अतः सेवा कर को लेकर 88 वाँ संविधान संशोधन किया गया।
अनु. 268 का प्रयोग करते हुए - ~~1997~~ 2003

4. VAT (मूल्य संवर्धित कर) : → सर्वप्रथम 1918 में जर्मनी में F. सिमेन्स के द्वारा VAT की शुरूआत की गयी (VAT के जनक)
परन्तु व्यवस्थाओं में कमी के कारण 1919 में इसे समाप्त कर दिया गया। तत्पश्चात् 1954 में इसे सफलतापूर्वक फ्रांस में लागू किया गया तथा 1967 तक VAT पूरे यूरोप में प्रसिद्ध हुआ।

→ भारत में माल के विक्रय पर लगने वाले कर के दोहराव से बचने के लिए 1976 में L.K. Jha समिति का गठन किया गया जिनकी सिफारिशों के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1981 में उत्पादन आधारित VAT (Manufacturing VAT) (आर. वेंकटरमन) लगाया गया।

→ उत्पादन आधारित VAT को बदलकर 2005 से भारत में P. चिदम्बरम के द्वारा सम्पूर्ण भारत में VAT लागू करने की घोषणा की।

→ VAT के लिए सर्वप्रथम हरियाणा राज्य ने अपनी सहमति दी।
सबसे अन्त में U.P. द्वारा सहमति।

(*) GST (Goods & Service Tax) 18% वर्तमान

→ वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगने वाले कर को जिसमें कर की दर एकसमान होती है।

→ प्रत्यक्ष कर प्रगतिशील होता है इसलिए इसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए जबकि अप्रत्यक्ष कर प्रगतिहीन कर होता है अतः इसकी मात्रा कम होनी चाहिए।
इसी सन्दर्भ में 2005 में विजय केलकर के नेतृत्व में GST को लागू करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने 115 वें संविधान संशोधन बिल के तहत जारी किया परन्तु संविधान संशोधन को लेकर तकनीकी एवं राजनैतिक समस्याओं के कारण यह बिल अभी तक लागू नहीं किया जा सका है।

NOTE GST को लेकर 115 वें संविधान संशोधन बिल में प्रस्तावित दर = 22%
परन्तु राज्यों के विवाद के कारण इस दर को कम करके 122 वें संशोधन बिल में 18% कर दिया गया। (इस पर भी आम सहमति नहीं है।)

NOTE भारत में मुद्रा-स्फीति के नियन्त्रण के लिए GST आवश्यक है क्योंकि भारत में उत्पादन की लागत कम है, परन्तु बाजार लागत अधिक।

- केन्द्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंध (अनुच्छेद 264-293) :-

→ वे कर जो केन्द्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं तथा वसूली व उपयोग राज्यों द्वारा किया जाता है।

→ इन करों में मुख्य कर हैं - स्टाम्प ड्यूटी, दवाओं पर लगने वाला शुल्क तथा प्रोसेसिंग चार्ज (प्रसंस्करण शुल्क)

→ वे कर जो केंद्र सरकार के द्वारा आरोपित किये जाते हैं तथा सम्पूर्ण राशि राज्यों को बांट दी जाती है।
eg. विज्ञापन कर, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्तियों पर लगने वाला कर

→ राज्य सरकार द्वारा आरोपित तथा राज्य सरकार को ही आवंटित कर
eg. टोल-टैक्स, एल्कॉहल पर कर, मनोरंजन कर

- GAAR (General Anti Avoidence Rules) :-

→ भारत में आने वाले विदेशी निवेश पर कर लगाने हेतु भारत सरकार के द्वारा (वित्त मंत्रालय) वर्ष 2010 में सर्वप्रथम GAAR संबंधी नियमों की घोषणा की गयी
ये नियम आयकर विभाग के अधिकारियों को शक्ति देते हैं कि भारत सरकार के कर संबंधी द्विपक्षीय समझौते के उल्लंघन करने वाले विदेशी निवेशकों पर कर आरोपित कर सकती हैं।

2010 में इसकी घोषणा के पश्चात विदेशी निवेश में काफी गिरावट आने लगी है इस समस्या से बचने के लिए "पार्थ सारथी सोम" (1 july 2012) समिति का गठन किया गया जिन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि वर्तमान परिस्थितियों में GAAR विदेशी निवेशकों के हितों में बाधा है अतः इसे 1 April 2016 से लागू

किया जाए। (वर्तमान बजट में इसे अगले वर्ष तक स्थगित कर दिया)

→

Scanned by CamScanner

# ☆ गरीबी एवं बेरोजगारी ☆

* **गरीबी (Poverty)** :→ गरीबी का तात्पर्य " सामान्यत: अभाव की स्थिति " से है अर्थात् अगर कोई व्यक्ति या समाज आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह समाज अथवा व्यक्ति गरीब कहलाता है।

→ UN के अनुसार – सामान्य जीवन जीने के लिए निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताएँ होती हैं

(1.) पेयजल
(2.) भोजन
(3.) आवास
(4.) स्वास्थ्य
(5.) शिक्षा

→ भारत में योजना आयोग / नीति आयोग के अनुसार सामान्य जीवन की निम्न न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं –

- (1.) जीवन
  - पेयजल
  - भोजन
- (2.) स्वास्थ्य
  - पोषणयुक्त भोजन
  - दवाएँ
- (3.) दक्षता
  - शिक्षा
  - कुशलता
  - सेवाएँ
    - बीमा
    - banking
    - परिवहन
    - ऊर्जा

**NOTE** भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग ( वर्तमान में नीति आयोग) के द्वारा किया जाता है तथा गरीबी के आँकड़े योजना आयोग को NSSO के द्वारा दिए जाते हैं।

Scanned by CamScanner

गरीबी के प्रकार :

गरीबी
- सापेक्षिक
- निरपेक्ष

**सापेक्षिक**

→ जब किन्हीं दो क्षेत्रों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन करके गरीबी का आकलन किया जाए।

जैसे :→ आय तथा जनसंख्या
→ दो देशों में तुलना

→ सापेक्षिक गरीबी विकसित देशों में मापी जाती है।

→ मापने की विधियाँ :-
(1.) लॉरेन्ज वक्र
(2.) गिनी गुणांक

**निरपेक्ष**

→ जब min. needs के आधार पर गरीबी का आकलन किया जाये।

→ भारत में इसी आधार पर गरीबी का आकलन होता है।

→ मापने की विधि :
सेन गुणांक

V.V.Imp

* सापेक्षिक गरीबी को मापने की विधियाँ :

1. लॉरेन्ज वक्र :→ मैक्स ओ लॉरेन्ज, 1905

Note विश्व में गरीबी का आकलन UNDP व WB द्वारा

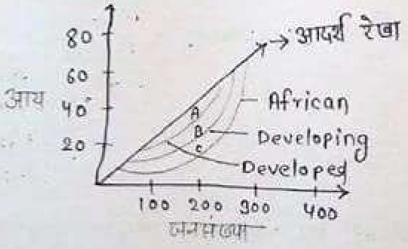


→ लारेन्ज वक्र के अनुसार, जो वर्ग आदर्श रेखा से जितनी अधिक दूरी पर होता है वह वर्ग उतना ही अधिक गरीब होता है तथा जो वर्ग आदर्श रेखा के जितना करीब होता है वह वर्ग उतना ही कम गरीब होता है।

2. गिनी गुणांक :

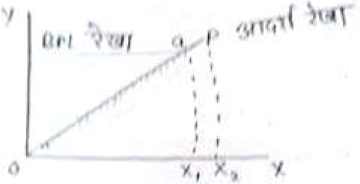


$$G = \frac{OQX_1 \text{ का क्षेत्रफल}}{OPX_2 \text{ का क्षेत्रफल}} \times 100$$

लॉरेन्ज वक्र का गणितीय रूप ही, गिनी गुणांक कहलाता है जिसका प्रतिपादन 1913 में इटली गणितज्ञ प्रोफेसर कोरेडो गिनी के द्वारा किया गया। इनके अनुसार G का मान गरीबी का मापक होता है।

जिस देश में G ↓ तो गरीबी ↓

एवं G ↑ तो आय की विषमता उतनी ही अधिक पायी जाती है।

→ भारत का गिनी गुणांक = 33.9% या 0.339

→ WB इसी आधार पर गरीबी का मूल्यांकन करता है।

* भारत में गरीबी का मापन :→

1. सेन गुणांक :→ 1978 में प्रो. अमर्त्य सेन के द्वारा सेन गुणांक प्रतिपादित किया गया जिनके अनुसार गरीबी रेखा से जो वर्ग जितना अधिक दूर होता है वह उतना ही अधिक गरीब माना जाता है ( सैद्धान्तिक नहीं )

→ भारत में अधिकृत रूप से गरीबी मापन के लिए सर्वप्रथम योजना आयोग के द्वारा 1971 में रथ व दाण्डेकर समिति का गठन किया गया जिन्होंने गरीबी को मापने के लिए कैलोरी को आधार माना।

इस समिति के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करता है तो वह गरीब है तथा यदि कोई शहरी व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम भोजन प्राप्त करता है तो वह गरीब है ( भोजन आधारित गरीबी )

→ सुरेश तेंदुलकर समिति (2009) :→ योजना आयोग ने सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जिन्होंने कैलोरी आधारित सूत्र को छोड़कर मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी को मापने का सुझाव दिया।

मासिक उपभोग व्यय

| Uniform Recall period सामान्य याद्दाश्त अवधि (URP) | Mixed Recall period (MRP) मिश्रित याद्दाश्त अवधि |
|---|---|
| → सर्वेक्षण से 30 दिनों पहले परिवार के (5 सदस्य) द्वारा गैर टिकाऊ वस्तुओं पर किया गया खर्च | → सर्वेक्षण से 365 दिन पहले तक टिकाऊ वस्तुओं (कपड़ा, जूता, अन्य) पर किया गया खर्च |

→ तेंदुलकर समिति के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र का कोई परिवार 1 माह में 4050 ₹ का व्यय कर रहा है तो वह परिवार गरीब नहीं है।

→ शहरी परिवार के लिए यह सीमा 4950 ₹ निर्धारित की गयी है।

→ इस समिति के अनुसार भारत में गरीबी 21.9 %
राजस्थान " 14.7 %

* सी. रंगराजन समिति :→ तेन्दुलकर समिति की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए May, 2012 में सी. रंगराजन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी जिन्होंने गरीबी के मापन का आधार वही रखा जो तेंदुलकर समिति ने रखा था परन्तु मासिक उपभोग की राशि में परिवर्तन किया गया।

रंगराजन समिति के अनुसार यदि ग्रामीण परिवार प्रतिमाह 4800 रुपए (32×5×30) से कम का उपभोग करता है तो वह गरीब परिवार है तथा यदि कोई शहरी परिवार प्रतिमाह 7050 रू. से (47×5×30) से कम का उपभोग करता है तो वह परिवार गरीब कहलाएगा अतः रंगराजन

समिति के अनुसार भारत में कुल 29.5% लोग गरीब है (ज्यादा ही बता दिये)

चूंकि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी 29.5 तथा TS के अनुसार गरीबी 21.9% अतः योजना आयोग ने TS के आधार पर ही गरीबी का मापन उचित समझा।

* गरीबी से जुड़ी अन्य Imp. समितियाँ :

(1.) T. लकड़ावाला समिति :→ इन्होंने केन्द्र, राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में गरीबी का अलग- अलग मापन करने की सलाह दी। (1978)

(2.) हासिम समिति (2013) :→ शहरों में BPL परिवारों का अलग से मापन

(3.) N.C. सक्सेना समिति (2010) → ग्रामीण क्षेत्रों में BPL परिवारों का अलग से मापन।

* गरीबी से जुड़े आंकड़े :→ (NSSO के 68 वें दौर के सर्वेक्षण के आधार पर

→ 1) सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य :→ छत्तीसगढ़ (39.93%)
→ दादर एवं नागर हवेली (39.31%)
→ झारखण्ड (36.93%)

2) न्यूनतम गरीबी वाले राज्य :→ अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह (1%)
→ लक्षद्वीप (2.77%)
→ गोवा (5.77%)

3) सर्वाधिक ग्रामीण गरीबी → दादर एवं नागर हवेली (62.59%)

4) सर्वाधिक शहरी गरीबी → मणिपुर (32.59%)

5) सर्वाधिक गरीब जनसंख्या → U.P.

बेरोजगारी :→ जब किसी व्यक्ति को योग्यता होने के बावजूद भी योग्यता के अनुरूप कार्य ना मिले तो ऐसी दशा बेरोजगारी कहलाती है। (योग्यता = काम करने की इच्छा)

→ सूत्र के आधार पर :-

श्रम बल - कार्य बल = बेरोजगारी

Note श्रम बल / शक्ति : जनसंख्या का वह भाग जो श्रम करने के योग्य हो।
(15 - 65 वर्ष तक की आयु का वर्ग)

कार्य बल : वे व्यक्ति जो किसी भी रूप में रोजगार से जुड़े हो।

→ बेरोजगारी की दर = $\frac{\text{श्रम बल - कार्य बल}}{\text{श्रम शक्ति}} \times 100$
(श्रम बल + कार्य बल)

NOTE WB के अनुसार भारत में बेरोजगारी की दर = 4.6%
अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार भारत -॥- = 3.8%
NSSO -॥- = 3%

Imp

बेरोजगारी के प्रकार :-

1) चक्रीय बेरोजगारी :-

जब अर्थव्यवस्था में मांग घटने से उत्पादन घट जाता हो व फलस्वरूप बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हो जाती हो। यह विकसित देशों में ज्यादा पायी जाती है। वाड्मेर में तेल आधारित।

2) घर्षण-जनित बेरोजगारी :→ जब रोजगार के पलायन के फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़े तो इसे घर्षण जनित बेरोजगारी कहते है। (भारत में कम) निजी / छोटी विज्ञापन / अच्छा काम करने

3) संरचनात्मक बेरोजगारी / तकनीकी :→ आधारभूत संरचनाओं मे कमी के फलस्वरूप जब बेरोजगारी बढ़े। (आदिवासी / पिछड़े / रिमोट एरिया ⇓ कुछ क्षेत्र)

- भारत में यह देखी जा सकती है।

4) अदृश्य / प्रछन्न बेरोजगारी :→ उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जिन्हें यदि उत्पादन से हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ता है तो ऐसे अतिरिक्त लोग अदृश्य बेरोजगार कहलाते हैं। कृषि

5) मौसमी बेरोजगारी :→ मौसम के अनुसार कार्य का मिलना अथवा मिलना। कृषि / मनोरंजन / मौसमी उद्योग

6) अल्प बेरोजगारी :→ जब लोगों को बहुत कम काम मिला हुआ हो।

7) शिक्षित बेरोजगारी :→ किसी कार्य के लिए जो min. शैक्षिक योग्यता होती है उसके होने के बावजूद भी जब काम ना मिले
B.Ed. & Engineering

8) खुली बेरोजगारी :→ बिल्कुल भी काम का न मिलना। (शहरों में)

Scanned by CamScanner

NOTE :- पूर्ण रोजगार की स्थिति :=> 1 वर्ष में 273 दिन का काम मिलना तथा 1 दिन में 4 घण्टे का काम मिलना।

* भारत में बेरोजगारी के कारण :->

1. धीमा आर्थिक विकास एवं तीव्र जनसंख्या वृद्धि
2. दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली
3. श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव
4. कुशल कार्यबल का अभाव
(ILO के अनुसार भारत में केवल 2% कुशल कार्यबल)
5. तकनीकी विकास का अभाव
6. कृषि का पिछड़ापन

* बेरोजगारी का मापन :

1. भागवती समिति (1973) का गठन किया गया। जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बेरोजगारी के मापन की निम्न 3 विधियों (आधार) का उल्लेख किया –

(i) सामान्य स्तर की बेरोजगारी :-> यदि किसी व्यक्ति को सम्पूर्ण वर्ष मे एक भी दिन काम ना मिले।
(बेरोजगारी का निम्नतम मान)

(ii) चालू साप्ताहिक स्तर की बेरोजगारी :-> यदि किसी व्यक्ति को पूरे 1 सप्ताह में 1 भी दिन काम ना मिले।
(बेरोजगारी का मध्यतम मान)

Scanned by CamScanner

(iii) चालू दैनिक स्तर की बेरोजगारी :→ यदि किसी व्यक्ति 1 पूरे दिन में 1 घण्टा भी काम न मिले।

(बेरोजगारी का उच्चतम मान)

* बेरोजगारी को दूर करने हेतु हाल ही की सरकारी योजनाएँ :→

1) (अप्रैल 2006) एकलव्य योजना :→ सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों को उन्हीं के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

2) चलो गाँव की ओर : (Feb. 2006) :→ राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ग्रामीण महिलाओं के नि:शुल्क कानूनी सहायता देने एवं उनकी जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य।

3) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (2014) :→ पं. दीनदयाल उपा. के 98 वें जन्मदिवस के उपलक्ष पर 15 - 35 वर्ष के ग्रामीण युवकों में कौशल का विकास करते हुए उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
(25 Sept 2014)

4) नई मंजिल योजना :→ 2015-16 के बजट में घोषित अल्पसंख्यकों को विकास से जोड़ना तथा उनका कौशल विकास करके रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य।

NOTE : अल्पसंख्यकों के तकनीकी एवं आर्थिक विकास के लिए MANAS (Molana Azad National Academy for skills नामक संस्था मौलाना आजाद [प्रथम शिक्षा मंत्री] के 125 वें जन्मदिवस (शिक्षा दिवस) पर 11 Nov. 2014 को शुरू स्थापित की गयी।

Scanned by CamScanner

# ☆ लोक वित्त ☆
## Public Finance

लोक वित्त : राज्य (सरकार) अपने दायित्वों को सार्वजनिक सत्ताओं (केंद्र एवं राज्य सरकार) के माध्यम से वित्तीय साधनों के द्वारा सम्पन्न करती है।

इन्हीं संस्थाओं (केन्द्र व राज्य) के वित्त से संबंधित सिद्धांतों, समस्याओं एवं नीतियों के विधिवत् अध्ययन को लोक वित्त कहा जाता है।

लोक वित्त को निम्न 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है -

1. सार्वजनिक आय : Already discussed (Budget)
2. सार्वजनिक व्यय :
3. सार्वजनिक ऋण : भारतीय सरकार की आय कम है तथा व्यय अधिक अतः इस घाटे को दूर करने के लिए तथा आधारभूत संरचनाओं का विकास करने के लिए सरकार घरेलू एवं विदेशी अल्पकालीन व दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है।

   घरेलू ऋण RBI एवं जनता से तथा विदेशी ऋण अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लिया जाता है ताकि सफल वित्तीय प्रशासन किया जा सके। ये समस्त ऋण सार्वजनिक ऋण कहलाते हैं।

4. वित्तीय प्रशासन : आर्थिक लेखा-जोखा → बजट
5. आर्थिक स्थिरता : देश में दीर्घकाल तक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के द्वारा राजकोषीय नीति (बजट एवं करारोपण) का निर्माण किया जाता है जिसका उद्देश्य आर्थिक नियमन को सफल बनाते हुए जनता को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करना है।

# ☆ वित्त - आयोग ☆

* (1.) स्थापना : संविधान के अनुच्छेद 280 (1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वें वर्ष (इससे पहले भी किया जा सकता है।)
वित्त आयोग का गठन किया जाता है।

NOTE भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन April 1951 में के.सी. नियोगी की अध्यक्षता में किया गया।

* वर्तमान में 14 वाँ वित्त आयोग Jan. 2013 में वाई. वी. रेड्डी (RBI के पूर्व गवर्नर) की अध्यक्षता में किया गया जिसने 24 Feb. 2015 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(2.) गठन का उद्देश्य :- वित्त आयोग निम्न आर्थिक विषयों पर राष्ट्रपति को सलाह देने के उद्देश्य से गठित किया जाता है।

1. केन्द्र की आय (कर) का राज्यों के साथ बँटवारा।
2. संचित निधि से राज्यों को मिलने वाले अनुदान की राशि।
3. पंचायती राज व्यवस्था में राज्यों का हिस्सा।
4. अन्य विषय – (जो राष्ट्रपति के द्वारा पूछे जाए)
   (i) जनोपयोगी सेवाओं के मूल्य निर्धारण संबंधी सलाह (पानी एवं बिजली की दर)
   (ii) GST
   (iii) राजकोषीय घाटे की समीक्षा करने हेतु
   (iv) संकटकालीन प्रबंधन से जुड़ी सलाह।
   (v) विनिवेश से संबंधित
   (vi) पोलावरम बांध से जुड़ा मसला (15 वें वित्त आयोग में जोड़ा गया) — आन्ध्र व तेलंगाना के मध्य विवाद

182

(xvii) पर्यावरण एवं चिरस्थायी विकास

☆ 14 वें वित्त आयोग की वर्तमान स्थिति :

① अध्यक्ष :- वाई. वी. रेड्डी

सदस्य :- प्रोफेसर अभिजीत सेन - अंशकालिक सदस्य
:- सुषमानाथ - पूर्व वित्त सचिव
:- डॉ. एम. गोविन्दो राव , डॉ. सुदिप्तो मुंडले , अर्जुन नारायण झा

14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट :

(1) कर के विभाजन को लेकर सिफारिश :-

ऊपर से नीचे ( समस्त राज्यों को दिये गये कर की कुल राशि )

सिफारिश 42% पहले 32% था।

विशिष्ट राज्यों को दिये गये कर की राशि

* विशिष्ट राज्यों को दिये गए कर की राशि का बँटवारा निम्न पाँच आधारों को ध्यान में रखते हुए किया जाये –

1. आबादी 1971 - 2011 को आधार माना है।
2. राज्यों की कुल प्रति व्यक्ति आय
3. वन क्षेत्र
4. क्षेत्रफल
5. वित्तीय अनुशासन

→ 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सर्वाधिक लाभान्वित राज्यों का क्रम :-
U.P. (1), बिहार (2), M.P. (3), प. बंगाल (4), महाराष्ट्र (5), राजस्थान (6)

Scanned by CamScanner

→ 14 वें वित्त आयोग के अनुसार निम्नलिखित करों में से राज्यों को हिस्सा दिया जाना चाहिए –

| राज्यों के साथ बाँटे जाने वाले कर | ना बाँटे जाने वाले कर |
| --- | --- |
| (i) निगम कर | अनुच्छेद 268 → स्टाम्प ड्यूटी तथा Alcohal पर उत्पाद कर |
| (ii) आय कर | |
| (iii) उत्पाद शुल्क | |
| Wealth (iv) सीमा शुल्क | अनु. 268 A : सर्विस टैक्स (केवल J&K में ST Applied नहीं) |
| (v) सेवा कर | |
| (vi) प्रतिभूति व्यवहार कर (STT) | अनु. 269 – केन्द्रीय विक्रय कर |
| (vii) धन कर (हटा दिया) | अनु. 270 – cess |
| | अनु. 271 – Surcharge |

→ केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि में राज्यों का हिस्सा

– ग्राम पंचायतों के लिए – 90 : 10 (CG : ST)

– शहरी निकायों के लिए – 80 : 10

→ आठ केन्द्र प्रयोजित योजनाओं में से केन्द्रीय सहयोग ना दिया जाये।

Scanned by CamScanner

# Share Market & Stock Exchange

प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था उस देश के वित्त बाजार पर निर्भर करती है जहाँ लोग अपने उद्देश्य के साथ वित्त का लेनदेन करते हैं। इस बाजार में निवेशक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा अपनी आवश्यकताओं के आधार पर इस बाजार के दो उपभागों को निर्धारित करते हैं
- मुद्रा बाजार
- पूंजी बाजार

मुद्रा बाजार :- वित्त बाजार का वह भाग जहाँ मौद्रिक प्रपत्रों का लेनदेन किया जाता है। मौद्रिक प्रपत्रों की निम्न विशेषताएँ होती हैं

(i) न्यूनतम जोखिम (ii) अल्पकालीन निवेश

(iii) न्यूनतम परन्तु निश्चित आय (iv) अत्यधिक तरलता

मौद्रिक प्रपत्रों के ex.→ T. Bill (Treasury bill) – न्यूनतम 30 दिनों के लिये जारी किये जाते हैं।
91 दिन, 182 दिन,
364/65 दिन

राष्ट्रीय बचत प्रपत्र, किसान विकास पत्र

पूंजी बाजार कित्त बाजार का वह भाग जो मुद्रा बाजार नहीं होता है। इस बाजार में पूंजी के प्रपत्रों का लेनदेन होता है। ये प्रपत्र कम्पनियों (निगमों) द्वारा जारी किये जाते हैं।

यदि कोई कम्पनी अपने जीवनकाल में पहली बार पूंजी के प्रपत्रों को जारी करती है तो ऐसा निर्गमन प्राथमिक बाजार का निर्गमन कहलाता है।

[illegible]

वह बाजार जहाँ प्राथमिक बाजार से खरीदे गए अंशों को बाजार मूल्य पर पुन: खरीदा अथवा बेचा जाता हो द्वितीयक बाजार कहलाता है जिसमें अंशों को खरीदने व बेचने की सुविधा स्टॉक एक्सचेंज नामक संस्था के द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

**NOTE** भारत में पूंजी बाजार की नियामक संस्था - SEBI (Securities and exchange board of India)

**SEBI** :-

1.) स्थापना :- वर्ष 1988 परन्तु वैधानिक शक्तियाँ SEBI अधिनियम 1992 के अन्तर्गत 12 अप्रैल 1992 को दी गयी।

2.) संरचना (9 सदस्य) :- एक चैयरमेन :- U. K. कुमार सिन्हा
:- एक अधिकारी RBI से।
:- दो अधिकारी, वाणिज्यिक एवं वित्त मंत्रालय से
:- पाँच अन्य अधिकारी (केन्द्र सरकार के द्वारा मनोनीत)

NOTE :- यदि केंद्र सरकार उचित समझे तो SEBI के सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है।

3.) प्रधान कार्यालय :- मुम्बई

Note: नैरोबी केन्या(अफ्रीका)

4.) स्थापना के उद्देश्य :- 1.) निवेशकों के हितों को सुरक्षा प्रदान करना
2.) पूंजी बाजार के मध्यस्थों को पंजीकृत करना
3.) भारत में प्रतिभूति बाजार का विकास करना

**NOTE** SEBI की स्थापना से पूर्व "पूंजी निर्गमन का नियंत्रक (CCI)" (1947 में स्थापित) नामक संस्था पूँजी बाजार का नियंत्रण करती थी
Controller of Capital Issues

10.6

5) शक्तियाँ :→

1) नियम जारी करने की शक्ति

2) मध्यस्थों को पंजीकृत करने की शक्ति तथा नियमों के उल्लंघन की दशा में पंजीकृत प्रमाण पत्र को निरस्त अथवा निलम्बित करने की शक्ति।

3) पूंजी बाजार के मध्यस्थों एवं सूचीबद्ध कम्पनियों से सूचना प्राप्त करने की शक्ति।

4) निवेशकों के हितों में दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति।

5) जाँच एवं अन्वेषण की शक्ति।

6) जुर्माना लगाने की शक्ति। (कारावास देने की शक्ति नहीं)

NOTE :→ * SEBI के द्वारा सर्वाधिक जुर्माना अंदरूनी व्यापार / भेदिया कारोबार की दशा में लगाया जाता है।

जुर्माने की राशि :- कमाये गये लाभ का 3 गुना अथवा 25 करोड़ रु (जो दोनों में अधिक हो)

* SEBI के आदेश के विरुद्ध 45 दिनों के भीतर प्रतिभूति अपीलीय ट्रिब्यूनल (SAT) नामक अर्द्ध-न्यायिक संस्था के समक्ष अपील दायर की जा सकती है

↳ SAT के आदेश के विरुद्ध 60 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। (SAHARA VS. SEBI)

* यदि कोई पक्षकार या संस्था SEBI के आदेशों का उल्लंघन करती है तो SEBI भी ऐसे पक्षकार अथवा संस्था के विरुद्ध अपील दायर कर सकती है।

Scanned by CamScanner

स्टॉक - एक्सचेंज :⇨ द्वितीयक बाजार की प्रमुख संस्था जो सूचीबद्ध कंपनियों के अंशों के बाजार मूल्य को प्रदर्शित करती है।

* Stock Ex. , SEBI के अधीन रहकर अपने पंजीकृत सदस्यों (दलाल) के माध्यम से अंशों के व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराती है।

* भारत में वर्तमान में 19 स्टॉक एक्सचेंज हैं। ( सभी केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त)
इनमें से प्रमुख S.E. निम्न हैं –

1) Bombay Stock Exchange of India Ltd. (BSE) :⇨

↳ स्थापना :- वर्ष 1875 ( एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज)
* इसके बाद एशिया में टोक्यो S.E. 1880
* विश्व का सबसे पुराना S.E. – एम्सटर्डम S.E (1602)

↳ सूचीबद्ध कम्पनियों की संख्या ( लगभग 5700) 5753
( सूचीबद्ध कम्पनियों के हिसाब से विश्व के प्रमुख 5 स्टॉक एक्सचेंज में शामिल)
(विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज – न्यूयॉर्क S.E. (America))

↳ BSE का सूचकांक :
SENSEX ( BSE का संवेदी सूचकांक) कहलाता है।
( यह नाम दीपक मोहनी के द्वारा दिया गया)

SENSEX :- BSE में सूचीबद्ध प्रमुख 30 कम्पनियों के अंशों के प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 1986 में ( आधार वर्ष 1978-79) BSE का सूचकांक जारी किया गया।

* ये प्रमुख 30 कम्पनियाँ 'ब्लू चिप' कम्पनियाँ कहलाती हैं।

Scanned by CamScanner

108

# BSE के अन्य सूचकांक :→ BSE-30 = SENSEX

1) BSE - DOLLEX :- डॉलर के मूल्य के बारे में जानकारी देने वाले सूचकांक

2) BSE - BANKEX :- बैंकिंग कम्पनियों के अंशों के मूल्य की जानकारी देने वाला सूचकांक

3) BSE - Small Cap :- B.S.E में सूचीबद्ध कम पूंजी वाली कम्पनियों के बारे में जानकारी देने वाला सूचकांक

4) BSE - Middle cap :- मध्यम पूंजी वाली कम्पनियों के अंशों की जानकारी देने वाला सूचकांक

4) ~~BSE - MIDDLE CAP~~ :-

## 2) National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) :⇒

1) फेरवानी समिति की सिफारिशों के आधार पर S.E. के व्यवहारों में पारदर्शिता लाने के लिये 1992 में प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के द्वारा NSE की स्थापना की गई।

2) कार्यालय : मुम्बई

3) देश का एकमात्र SE जो प्रतिभूति बाजार के समस्त क्षेत्रों में online व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।

Note: प्रतिभूति बाजार के क्षेत्र :- (i) Cash Segment (समता पूंजी के लिए)
FED (ii) Future Segment (भावी मूल्यों के लिये व्यवहार)
CED (iii) Currency Segment / विदेशी मुद्रा के

Scanned by CamScanner

NSE का सूचकांक :- NIFTY (= 50 कम्पनी) के नाम से जाना जाता है

BSE : 30 :: NSE : 50
↓ ↓
SENSEX NIFTY

→ सूचीबद्ध कम्पनियों की संख्या :→ लगभग 2600

शेयर बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द :⇨

(i) तेजड़िया व मंदड़िया बाजार :↳ शेयर बाजार के भावी मूल्यों को लेकर जिस बाजार में तेजी की आशंका हो, अंशों को खरीदा जाता हो, तेजड़िया तथा जिस बाजार में मंदी की आशंका से अंशों को बेचा जाता हो मंदड़िया बाजार कहलाती है।

(ii) हैजिंग :↳ निवेश की वह तकनीक जिसमें निवेशक अपनी सम्भावित हानि को सम्भावित लाभ से कम करता हो।

Note ऐसे निवेशकों का उद्देश्य, लाभ कमाना नहीं होता बल्कि न्यूनतम हानि को करना होता है।

(iii) Mutual fund :↳ SEBI के द्वारा पंजीकृत किया गया कोष जो अपनी यूनिट (अंश) जनता को बेचकर पैसा प्राप्त करता है तथा प्राप्त पैसे को अलग-अलग क्षेत्रों में निवेश करके प्राप्त लाभ को यूनिट धारकों में बाँट दिया जाता हो।

(iv) जोखिम पूंजी कोष (Venture capital fund) सेबी के द्वारा पंजीकृत एक कोष जो अपनी यूनिट बेचकर प्राप्त रकम को नई एवं विकास की ओर अग्रसर कम्पनियों को दीर्घकालीन पूंजी के रूप में निवेशित करता है। ऐसी कम्पनियाँ स्टार्ट-अप कम्पनियों के नाम से जानी जाती है।

110

(v) भागीदारी नोट ( Participatory Note) (P-Note)

:-> विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा विदेशी निवेशकों को जारी किये गये प्रपत्र जिन्हें खरीदकर विदेशी निवेशक आसानी से भारतीय पूंजी बाजार में अप्रत्यक्ष निवेश करने के योग्य हो जाता है। मनी लांड्रिंग को बढ़ावा देने के कारण SEBI ने इनके निवेश की मात्रा को कम किया है।

(vi) वायदा बाजार आयोग (Forward market commission) (FMC)

वायदा बाजार :- ऐसी वस्तुएँ जिनके बाजार मूल्य में निरन्तर उतार-चढ़ाव रहता है, पूंजी बाजार में commodity के नाम से जानी जाती है। कमोडिटी के भविष्य के मूल्य के आधार पर वर्तमान में जिस बाजार में व्यापार किया जाता हो, वायदा बाजार कहलाता है। भारत में वायदा बाजार की नियामक संस्था FMC थी जिसका हाल ही में (Sept. 2015) सेबी में विलय कर दिया गया (SEBI के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि) इसकी स्थापना 1952 में की गई।

Commodity के eg. → धातु-आधारित (सोना, चाँदी, ताँबा, Al etc.)

→ खाद्यान्न आधारित (ग्वार, चना, सरसों

→ प्राकृतिक वस्तुओं पर आधारित (कच्चा तेल).

→ विदेशी मुद्रा etc.

Scanned by CamScanner

# ☆ भारत में औद्योगिक क्षेत्र ☆

प्रत्येक अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र विशेष महत्व रखता है क्योंकि औद्योगिक विकास से नये उत्पाद, तकनीकि, सेवाएँ अर्थव्यवस्था में प्रवेश करती है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास से देश की राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया।

↓

प्राथमिक उत्पादों को द्वितीयक उत्पाद में बदलना ही। भारत में औद्योगिक के विकास के लिये सरकार ने समय-समय पर कई औद्योगिक नीतियाँ बनायी है जो निम्न हैं—

(1) औद्योगिक नीति 1948 : ↳ 1) प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 April 1948 को प्रथम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गयी

2) इस औद्योगिक नीति में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया।

3) उद्योगों को चार वर्गों में बाँटा गया -

प्रथम वर्ग → सैनिक एवं राष्ट्र महत्व के उद्योग
→ eg. अणु, अस्त्र-शस्त्र, रेल उद्योग etc.

द्वितीय वर्ग → इस वर्ग में प्रमुख 6 उद्योगों को आधारभूत संरचना के उद्योग के रूप में शामिल किया गया।
↓
लौह-इस्पात, कोयला, टेलिफोन, वायुयान निर्माण, जहाजरानी निर्माण, खनिज तेल।

तृतीय वर्ग → निजी क्षेत्र के सहयोग से 18 उद्योगों को इस वर्ग में जोड़ा गया। (Govt + pvt)

चतुर्थ वर्ग → शेष उद्योग, जो 1956 में स्थापित करने के उद्देश्य रखे गये।

11

(2) औद्योगिक नीति 1956 :⇨ इस औद्योगिक नीति की घोषणा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में की गई। यह औद्योगिक नीति महालनोबिस-नेहरू मॉडल पर आधारित है जिसमें सर्वप्रथम भारी उद्योगों के विकास पर बल दिया गया तथा प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में सरकारी नियन्त्रण की बात कही गई। इस नीति में उद्योगों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया :-

1] आधारभूत के 17 उद्योग तथा इन उद्योगों में सरकारी नियंत्रण का प्रस्ताव रखा गया

2] इस श्रेणी में मुख्य 12 उद्योगों को रखा गया (सीमेंट, कागज, नमक, चीनी etc.) जो राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत हो।

3] तृतीय वर्ग : शेष उद्योग, जो निजी सहयोग से स्थापित किये जा सके।

NOTE इस औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान कहा जाता है जो समाजवादी मॉडल पर आधारित है (USSR से अपनाया गया)

(3) औद्योगिक नीति 1977 (23 Dec.) (मोरारजी देसाई) इस औद्योगिक नीति में सर्वप्रथम लघु एवं कुटीर उद्योगों पर विशेष जोर दिया गया तथा साथ ही 1 lakh तक की पूंजी वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग के रूप में पहचान दी गयी।

→ यह नीति गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रभावित थी (ग्रामीण उद्योगों पर अधिक जोर)

→ लघु उद्यमियों को एकल खिड़की योजना के अन्तर्गत आर्थिक, तकनीकी एवं कानूनी सहायता देने के उद्देश्य से जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गयी।

Scanned by CamScanner

(4) औद्योगिक नीति (23 July 1980)

:→ इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस औद्योगिक नीति की घोषणा की गई जिसमें सार्वजनिक उद्योगों के कुशल प्रबंधन पर जोर दिया गया।

:→ जिला उद्योग केन्द्रों को क्रियान्वित रखा गया तथा लघु व कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया।

(5) औद्योगिक नीति (24 July 1991)

:→ राव - मनमोहन मॉडल पर आधारित है।

:→ L, P एवं G मॉडल से प्रभावित

:→ उच्च प्रौद्योगिकी एवं उच्च निवेश पर विशेष ध्यान दिया गया।

:→ 8 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर शेष उद्योगों की स्थापना के लिये अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया। (इस संख्या को घटाकर 6 कर दिया गया)

:→ उच्च निवेश के लिये विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया।
वे उद्योग जो लगातार हानि में चल रहे हैं के पुनरूत्थान के लिये वित्त प्रबंधन की व्यवस्था की गयी।

:→ पूँजी की तरलता को बढ़ाने के लिये राष्ट्रीय स्तर के S.E (stock Exchange) के माध्यम से शेयर बाजार के विकास पर अधिक जोर दिया गया।

:→ नए उद्योगों की स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।

☆ 1991 के पश्चात औद्योगिक क्षेत्र में आधुनिक पहल :→

1] राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (नयी) 4 नव. 2011 :

:→ औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से 2011 में नई विनिर्माण नीति बनायी गयी जिसमें देश की GDP में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को 25% तक रखने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया।

:→ रोजगार में 10% अतिरिक्त वृद्धि का लक्ष्य।

:→ चिरस्थायी विकास की संकल्पना।

:→ विनिर्माण क्षेत्र में निवेश तथा निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए पूरे देश में 8 'राष्ट्रीय निवेश व निर्माण क्षेत्र' (NIMZ) (औद्योगिक शहर) की स्थापना की गई।

NOTE: राजस्थान के 2 क्षेत्र NIMZ में शामिल हैं–

(1.) भिवाड़ी, नीमराणा

(2.) जोधपुर-पाली, मारवाड़ क्षेत्र

2] मिनीरत्न, महारत्न एवं नवरत्न योजना :-

:↳ मिनीरत्न योजना : → वर्ष 1997 में शुरू

:→ नवरत्न कम्पनियों के अलावा लगातार मुनाफा कमा रहे उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु इस योजना को शुरू किया गया।

इस श्रेणी में आने वाली औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय संचालन एवं प्रबन्धन में सरकार के द्वारा स्वतंत्रता प्रदान की गयी।

:→ इस योजना में उन औद्योगिक इकाईयों को शामिल किया जाता है जिनका लाभ विगत वर्ष में 30 करोड़ या उससे अधिक हो।

:→ वर्तमान में इनकी संख्या = 72

Scanned by CamScanner

:↳ नवरत्न योजना :

:→ वर्ष 1997 में शुरू।

:→ वे सार्वजनिक उपक्रम जिनमें ग्लोबल होने की संभावना हो, नवरत्न का दर्जा दिया जाता है।

:→ नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए 100 अंकों के मापदण्ड में से ऐसी इकाईयों को न्यूनतम 60 अंक प्राप्त करने होते हैं, जो निम्न आधारों पर मूल्यांकित किये जाते हैं — (i) सम्पत्ति (कुल संपत्तियों से 50% सम्पत्ति विपणन योग्य होनी आवश्यक)

(ii) पूँजी (iii) शुद्ध कीमत

(iv) प्रति अंश अर्जित आय (v) लाभ

NOTE: नवरत्न कंपनियाँ बिना सरकार की अनुमति के अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निवेश कर सकती हैं तथा साथ ही घरेलू बाजार की तरह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से पूँजी जुटा सकती हैं।

:→ वर्तमान में संख्या = 17

:↳ महारत्न योजना, 2009 :→ नवरत्न कंपनियों में से वे कम्पनियाँ जो निम्न मापदण्डों को पूरा करती हो, को महारत्न का दर्जा दिया जाता है।

(i) पिछले 3 वर्षों तक लगातार सूचीबद्ध हो।

(ii) पिछले 3 वर्षों में औसत विक्रय - min. 20,000 करोड़

(iii) शुद्ध लाभ - 2500 करोड़

(iv) पिछले 3 वर्षों की शुद्ध कीमत - min. 15000 करोड़

(v) विदेश में कारोबार होना आवश्यक

NOTE वर्तमान में भारत में संख्या - 7

Scanned by CamScanner

1. BHEL → Bharat heavy electricals limited
2. SAIL → steel authority of india limited
3. GAIL → Gas —〃—
4. Coal Ind. Ltd.
5. ONGC → Oil and Natural gas corporataion → largest
6. NTPC → National thermal power corporation
7. IOC → Indian Oil Corporation

3.] विशेष औद्योगिक गलियारे : तीव्र औद्योगिक विकास के लिये सरकार के द्वारा इनकी स्थापना की गयी ताकि विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाया जा सके तथा कम समय व लागत में औद्योगिक उत्पादन के आवागमन को सरल बनाया जा सके।

★ भारत के प्रमुख औद्योगिक गलियारे :-

1.] दिल्ली - मुम्बई औद्योगिक गलियारा :→ जापान के सहयोग से दिल्ली से मुम्बई तक आधारभूत ढाँचे को विकसित करने के लिये तथा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस परियोजना को शुरू किया गया।

NOTE April, 2016 में राज. सरकार ने इस परियोजना में निवेश संबंधी अधिनियम पारित किया।

2] चेन्नई - बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा :> कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य में 560 km तक फैला हुआ गलियारा। इसका निर्माण जापान के सहयोग से।

Scanned by CamScanner

117

3.] बेंगलुरू - मुम्बई गलियारा :
→ Feb 2013 को U.K. के सहयोग से इस परियोजना को लागू किया गया।

4.] अमृतसर - दिल्ली - कोलकाता गलियारा :→ पंजाब, हरियाणा, U.P., उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड एवं प. बंगाल में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा 20 Jan. 2014 को इस योजना को शुरू किया गया।

Scanned by CamScanner

★ राष्ट्रीय निवेश कोष ★
{NIF}

:→ 6 oct 2007 से इस कोष ने कार्य शुरू किया। ( स्थापना 2005

:→ सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश एवं लाभांश से प्राप्त होने वाले राजस्व के सुनियोजित उपयोग के लिये इस कोष की स्थापना की गई।

:→ इस कोष में जमा राशि संचित निधि में नहीं जाता है, अतः इसका उपयोग करना सरल है।

:→ इस कोष में जमा राशि का 75% भाग स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिये किया जाता है तथा शेष 25% भाग सार्वजनिक इकाईयों में निवेश किया जाता है।

:→ इस कोष का प्रबंधन निम्न तीन कम्पनियों के द्वारा किया जाता है –

(i) UTI ( Unit Trust of India)
(ii) SBI
(iii) LIC

4.) कम्पनी अधिनियम 2013 में सामाजिक उत्तरदायित्व से सम्बन्धित नियम (CSR)

कम्पनियों के माध्यम से सामाजिक विकास को बढ़ावा देने तथा आर्थिक-सामा. वृद्धि में संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम 2013 में कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के लिये उनके सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया है।

ये नियम निम्न कम्पनियों पर लागू होते हैं –

(i) प्रत्येक कम्पनी जिसका किसी वित्तीय वर्ष में शुद्ध लाभ 5 करोड़ ₹ अथवा अधिक हो

अथवा

(ii) जिसका पिछले 3 वर्षों का औसत विक्रय 500 करोड़ ₹ अथवा अधिक है

- 118.

अथवा

(iii) जिसकी शुद्ध कीमत 100 करोड़ रु. अधिक हो

अथवा

उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करने वाली कम्पनी को अपने विगत 3 वर्षों के औसत लाभ का 2% सामा: कल्याण के कार्यों में निवेश करना अनिवार्य है, यदि संचालक निवेश नहीं कर पाते है तो लिखित रिपोर्ट में निवेश ना करने सम्बन्धी कारण केन्द्रीय सरकार को बताना आवश्यक अन्यथा दोषी संचालक पर 2 साल की जेल अथवा 25 लाख तक जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान।

**स्टैण्ड - अप इण्डिया योजना** :⇒ 6 जनवरी 2016 को SC एवं ST तथा महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ाने के लिये केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने इस योजना को मंजूरी दी।

→ इस योजना में लक्षित वर्ग के लिए सस्ती दरों पर 7 वर्ष की अवधि के लिये उद्यमिता ऋण देने का प्रावधान किया गया है।

→ प्रति महिला उद्यमी को 10 लाख से 10 करोड़ रु तक के ऋण का लक्ष्य रखा गया है।

इस योजना में 10,000 करोड़ रु की राशि ~~SEBI~~ SIDBI (Small industrial development bank of India)

**स्टार्ट - अप इण्डिया** :⇒ 16 जनवरी 2016 को नए उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस योजना की शुरूआत की गई।

:→ योजना में दिये जाने वाले ऋण के लिए स्टार्ट अप फण्ड की स्थापना की गयी है जिसमें 10,000 करोड़ रु का निवेश किया जाएगा।

Scanned by CamScanner

स्टॅण्ड - अप इण्डिया

:→ स्टार्ट - अप उद्योगों को प्रथम तीन वर्ष तक कई प्रकार की सहायताएँ देने का प्रावधान रखा गया है।

(i) पेटेन्ट शुल्क में 80% तक की छूट।

(ii) प्रथम 3 वर्षों में कर से मुक्ति।

(iii) श्रम एवं पर्यावरण कानून में सरलता।

Imp.

NOTE : नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 150 करोड़ की प्रस्तावित योजना — अटल इनोवेशन मिशन (Current Update)

(5) भारत में औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण समितियाँ :-

1. तिवारी समिति 1981 :→ औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के लिये ~~SICA~~ SICA (~~Sich~~ Sick industrial companies Act) 1985 की शुरुआत

2. मीरा सेठ समिति 1997 :→ हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिये हस्तशिल्प ऋण कोष की स्थापना की गयी।

3. आबिद हुसैन समिति 1997 :→ लघु उद्योगों ~~की~~ में आरक्षण की समाप्ति

4. बालकृष्ण ईराडी समिति 2000 :→ नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) की स्थापना की सिफारिश। (अभी तक स्थापित नहीं हो सका) (रूपरेखा तैयार हुयी)

Scanned by CamScanner

5. सी. रंगराजन समिति :→ चीनी उद्योग में सरकारी नियंत्रण की
(2012) समाप्ति।

6. N.R. नारायणमूर्ति समिति (2001) :- सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कॉरपोरेट शासन संबंधी नियमों की व्यवस्था।

Scanned by CamScanner

122

# ★ भारत में कृषि ★

* कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है जिसमें कृषि के साथ उसके सम्बन्ध क्षेत्रों ( पशुपालन एवं बागवानी ) भी शामिल है।

* कुल श्रम शक्ति का 48.9% हिस्सा कृषि पर आश्रित है।

* कुल निर्यातों में 14% निर्यात कृषि से।

* GDP में कृषि का योगदान निरन्तर घट रहा है।

* 12 वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि में 4% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया ( 11 वीं में भी यही लक्ष्य था )
  वास्तविक वृद्धि 3.6%

* प्रमुख कृषि निर्यातक उत्पाद :→ कॉफी, चाय, चावल (बासमती), तेल काजू, गरम मसाले, कपास

* भारतीय कृषि और फसल :→

1. रबी फसल → अक्टूबर - नवम्बर में बुवाई, अप्रैल - मई में कटाई

   गेहूं, जौं, सरसों, मटर, राई

2. खरीफ फसल → जून - जुलाई में बुवाई, Sept oct कटाई

   ज्वार, बाजरा, चावल, मक्का, कपास, तम्बाकू, मूंगफली, मूंग व उड़द

Scanned by CamScanner

123

3. जायद :- मार्च बुवाई , जून कटाई

∴ सब्जियाँ प्रमुख , तरबूज , ककड़ी etc.

* फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण :-

1. खाद्यान्न फसलें :→ भरण-पोषण एवं भोजन के लिये उगाया

इन्हें निम्न 3 उपभागों में बाँटा जा सकता है -

1. प्रमुख खाद्यान्न ( गेहूँ , धान , जौ )
2. मोटे अनाज ( बाजरा , ज्वार )
3. लघु खाद्यान्न ( चना , काकून , रागी )

2. व्यापारिक फसल :→ इनको उगाने का उद्देश्य धन प्राप्त करना या तो इन्हें पूर्ण रूप से बेच दिया जाता है या आंशिक उपभोग करके अधिकांश हिस्सा बेच दिया जाता है।

→ इनमें तिलहन फसलें प्रमुख है। चाय; गन्ना etc.

* कृषि से जुड़ी पहल :→

1. राष्ट्रीय बीज मिशन (NSM) :- 12 वीं पंचवर्षीय योजना में बीजों की तकनीक एवं किस्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बीज मिशन योजना शुरू की गई।

11 वीं पंचवर्षीय योजना में 1 April 2007 को वाराणसी राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापित किया जो बीजों की किस्म की

Scanned by CamScanner

प्रयोगशाला के रूप में स्थापित है।

NOTE ज्यूरिख (Switzer.) में स्थित अन्तर्राष्ट्रीय बीज. परीक्षण में भारत की इसी Lab. को सदस्य Lab के रूप में मान्यता दी गई है।

2. उर्वरक नीति :- यूरिया < USA, China, India { उत्पादन में I[st], खपत में II[nd]

यूरिया में निवेश की मात्रा को बढ़ाने के उद्देश्य से नयी निवेश नीति 2012 बनाई गयी जिसका प्रमुख उद्देश्य यूरिया की गुणवत्ता में सुधार करना तथा कम लागत पर किसानों को उच्च गुणवत्ता की यूरिया उपलब्ध कराना है। (WTO की बालि शिखर वार्ता में विवाद का प्रमुख कारण)

3. कृषि साख : भारत में कृषि पर मिलने वाली साख के निम्न दो प्रारूप हैं-

1. गैर संस्थागत स्त्रोत (सेठ, साहूकार, महाजन, very bad)
2. संस्थागत प्रारूप (Bank, सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार)

Note : किसानों को खेती के लिये तथा ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से शिवरमन समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में 12 जुलाई 1982 को NABARD की स्थापना की गयी। (मुम्बई)

यह संस्था ग्रामीण विकास के लिये ग्रामीण लोगों को अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के माध्यम से)

Scanned by CamScanner

4. कृषि विपणन : फसलों को बाजार तक पहुँचाने की समस्त क्रियाएँ कृषि विपणन में शामिल होती हैं।

इस क्षेत्र में व्याप्त कमियों को दूर करने के लिये स्वतन्त्रता प्राप्ति से अब तक निम्न पहल की गई है –

1. न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP
2. भारतीय खाद्य निगम (FCI) 1965
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) 1966
4. ट्राईफेड (भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ) (Tribal cooperative marketing development federation of india limited)

:→ जनजाति लोगों को निजी व्यापारियों के शोषण से छुटकारा दिलाने हेतु इस संस्था की स्थापना अगस्त 1987 (कार्य प्रारंभ अप्रैल 1988) में की गयी।

:→ यह संस्था जनजातिय लोगों को शिक्षा, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है उनका विकास करने में संलग्न है।

5. कृषि में आयात व निर्यात :→

1. शीर्ष निर्यात
2. शीर्ष आयात :- वनस्पति तेल, कच्चा कपास, फल, दूध, क्रीम, काजू etc.

3. कुल निर्यात :- 15%
   कुल आयात :- 6%

Scanned by CamScanner

126

कृषि में निर्यातों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार के द्वारा कृषि निर्यात क्षेत्रों (AEZ) की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत के 46 क्षेत्र AEZ नाम से निर्यातकों के रूप में भूमिका निभाते हैं जिनमें निम्न क्षेत्र प्रमुख हैं -

(i) M.P. - मसाले

(ii) उत्तराखण्ड व पंजाब - बासमती चावल (भारत, Pak व BAN में GI को लेकर विवाद)

(iii) पश्चिमी बंगाल व तमिलनाडु - आम

(iv) झारखण्ड - सब्जी

(v) ओड़िशा - अदरक एवं हल्दी

(vi) महाराष्ट्र - प्याज

Note राजस्थान प्रस्तावित - आँवला

6. निर्यात सब्सिडी किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार समय-समय पर उर्वरक, बीज व सिंचाई पर सब्सिडी प्रदान करती आयी है परन्तु 2013 के पश्चात WTO के बढ़ते दबाव के कारण सब्सिडी की मात्रा निरन्तर कम की जा रही है।

Scanned by CamScanner

कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योजनाएँ :

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : 14 जनवरी 2016
: किसानों की आय को 2022 तक ( स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ तक) दोगुना करने के उद्देश्य से तथा 13.5 करोड़ किसानों को फसल बीमा के रूप में सुरक्षा कवच देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया।

2. मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 5 दिस 2015
↓
(विश्व मृदा दिवस) के उपलक्ष्य पर

प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से तथा मिट्टी से जुड़ी आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया।
इस योजना में 14 करोड़ मृदा कार्ड जारी किये जायेंगे।
गंगानगर से प्रारम्भ

नारा - "स्वस्थ धरा खेत धरा"

3. नीरांचल स्मरण योजना 7 Oct 2015 को WB के सहयोग से 2142 करोड़ रु की लागत से भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओड़िशा, महाराष्ट्र, झारखण्ड, M.P, राजस्थान एवं गुजरात में जल के अधिकतम उपयोग को बढ़ाने एवं सिंचाई का लाभ देने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2 july 2015) को 5000 करोड़ की लागत से सिंचाई के साधनों में निवेश करके खेतों में पानी की दक्षता को बढ़ाना तथा पानी के अपव्यय को रोकने के लिये श्री मोदी के द्वारा इस योजना शुरू किया गया।

नारा - "हर खेत को पानी"

Scanned by CamScanner